● वर्ष-4
● अंक-100
रायपुर, गुरुवार
05 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» रुतबेदार विकल्प है वकालत

महायुति ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

फडणवीस बोले- हम साथ मिलकर काम करेंगे

मुंबई। महाराष्ट्र में सीएम पद और सरकार गठन को लेकर चल रहा इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। महायुति नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। महायुति में शामिल भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार ने राजभवन में राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इस दौरान राज्य के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस पांच दिसंबर को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। हमारे गठबंधन सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि मुझे महायुति के सीएम के रूप में शपथ दिलाई जाए। राज्यपाल ने सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए हैं और हमें कल शाम 5.30 बजे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम का समर्थन किया है। एनसीपी नेता अजित पवार ने भी मेरे नाम की सिफारिश की। सीएम, डिप्टी सीएम सिर्फ तकनीकी पद हैं। पिछले ढाई साल में हमने साथ मिलकर काम किया है। आगे भी हम सब मिलकर अच्छी सरकार देने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हमने जो वादे जनता से किए हैं वे हम पूरे करें। महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पूरा करेंगे। अन्य

मंत्रियों के नाम पर आगामी बैठकों में फैसला लिया जाएगा। हम शाम तक तय करेंगे कि कल कौन शपथ लेगा।

फडणवीस ने कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि महायुति कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वह इस सरकार में हमारे साथ रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे साथ रहेंगे। हम महाराष्ट्र की जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाने वाले रामदास अठावले, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हम महाराष्ट्र को नया विजन देंगे। इसके बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि हम सर्वोत्तम राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली मैं किसी निजी काम से गया था। हम अच्छी सरकार देंगे। मैं तो शपथ लेने वाला हूं। हम राज्य में सरकार चलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। पार्टी से संबंधित गतिविधियों को भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और एनसीपी के सुनील तटकरे संभालेंगे।

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज हमने राज्यपाल को मिलकर सरकार बनाने की अनुमति मांगी है। राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है। कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। देवेंद्र मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने उनको समर्थन दिया है। उनको शुभकामनाएं। मैंने पूर्ण समर्थन की घोषणा पहले ही कर दी थी। ढाई साल पूरे होने पर मैं बहुत खुश हूं। पिछले 2.5 सालों में महायुति सरकार, हम तीनों और हमारी टीम ने जो काम किया है, वो उल्लेखनीय है। इसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शिंदे ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने इतने बड़े फैसले लिए। इतिहास में इतना भारी बहुमत किसी को नहीं मिला है। महाराष्ट्र की बहनों ने हमारा साथ दिया। हमने ढाई साल जनता के लिए काम किया। एमवीए ने जो काम रोके उसे हम आगे ले गए। हमने कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। डबल इंजन की सरकार से जनता को फायदा हुआ। महायुति में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। हम एक टीम के तौर पर काम करेंगे। नई सरकार को अधिक काम करना होगा।

दादा को सुबह और शाम को शपथ लेने का अनुभव- शिंदे

महायुति के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित होने के कुछ घंटों बाद, देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि वह कल (5 दिसंबर) शाम 5.30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच मजाकिया लहजे में नोकझोंक देखने को मिली। महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे से पूछा गया कि क्या वह देवेन्द्र फड़णवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होंगे।

निवेशकों के लिए खुला रेड कारपेटः साय

27 बड़े औद्योगिक समूहों को 32 हजार 225 करोड़ रुपए के नवीन पूंजी निवेश के लिए प्रदान किए गए 'इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर'

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स का विपुल भंडार है, अनुकूल औद्योगिक वातावरण है, साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है। निवेश की जटिलताएं अब छत्तीसगढ़ में नहीं रही। सिंगल विंडों सिस्टम ने सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से ''छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम (स्टेक होल्डर कनेक्ट वर्कशॉप)'' को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है। इसके लिए हमें विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत का

भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेकर किया गया है। नई नीति तैयार करने में उद्योगपतियों से सुझावों को शामिल किया गया है। इस नीति से प्रदेश में निवेश तो आएगा ही, नये उद्योगों की स्थापना होगी, साथ ही राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ के नवीन औद्योगिक नीति की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। इस नीति से प्रदेश में सस्टेनेबल औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। नई नीति में एमएसएमई उद्योगों को सशक्त बनाने का अच्छा प्रयास किया गया है। नये क्षेत्रों में निवेश के लिए इंसेन्टिव स्कीम तैयार की गई है। इस उद्योग नीति में रोजगार सृजन महत्वपूर्ण पहलू है। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में राज्य के 27 बड़े औद्योगिक समूहों को नवीन पूंजी निवेश के प्रस्ताव के संबंध में 32 हजार 225 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर प्रदान किए। इनमें राज्य के कोर सेक्टर के साथ ही नये निवेश क्षेत्रों जैसे आईटी, एआई, डाटा सेंटर, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्रेस्ड बायो गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री से की सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे गृह मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों की हालिया उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों के सम्बन्ध में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया।

सावधि जमा में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की छूट मिलेगी

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया। यह विधेयक बैंकिंग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इस बिल के पारित होने के बाद जमाकर्ताओं को अपने बैंक और सावधि जमा खातों में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की छूट मिल सकेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के निचले सदन में अपने संबोधन में कहा, आज बैंकों को पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है। मेट्रिक्स स्वस्थ हैं, इसलिए वे बाजार में जा सकते हैं और बॉन्ड जुटा सकते हैं, ऋण जुटा सकते हैं और अपने व्यवसाय को उसी के अनुसार चला सकते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण के अनुसार मौजूदा नियमों के तहत जमाकर्ता के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट या लॉकर में रखे सामान के लिए केवल एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की अनुमति थी, लेकिन अब जमाकर्ताओं के पास एक के बाद किसी अन्य को या एक ही समय में अपने बैंक अकाउंट में चार अलग-अलग नॉमिनी जोड़ने का विकल्प होगा।

बैंक खातों में एक से अधिक नॉमिनी जोड़ने देने के फैसले का उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु के बाद निधि वितरण को सरल बनाना है, यह एक ऐसी समस्या है जो कोविड महामारी के दौरान पैदा हुई थी। विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण सुधारों में बैंक निदेशक पद के लिए भुगतेय राशि को फिर से परिभाषित करना भी शामिल है। पहले इस मद में अधिकतम 5 लाख रुपये खर्च करने की सीमा थी अब इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है। यह आंकड़ा लगभग छह दशकों से अपरिवर्तित है।

नए प्रावधान बैंकों को वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने में अधिक स्वतंत्रता देते हैं और नियामक रिपोर्टिंग की समयसीमा को मौजूदा दूसरे और चौथे शुक्रवार की जगह हर महीने की 15वीं और आखिरी तारीख के लिए संशोधित किया गया है।

प्रमुख समाचार

महापंचायत के लिए नोएडा जा रहे थे राकेश टिकैत

अलीगढ़। यूपी पुलिस ने बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत को अलीगढ़ में हिरासत में ले लिया। इस बीच, टिकैत ने धमकी दी कि अगर सरकार ने आज शाम तक उन्हें जवाब नहीं दिया तो वे लखनऊ तक ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। किसान सरकार द्वारा अधिग्रहीत अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दलित प्रेरणा स्थल के पास रोक दिया, जिसके बाद वे वहीं धरने पर बैठ गये। टिकैत ने कहा कि हमें नहीं पता कि वे हमें कहां ले जा रहे हैं। अगर वे समाधान नहीं निकालेंगे तो हम यहां से लखनऊ तक ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। हम आज शाम तक सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। पुलिस ने मंगलवार को नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर यादव खलीफा समेत 160 से अधिक प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर सोमवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से गौतम बौद्ध नगर में एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर राष्ट्रीय राजधानी तक अपना मार्च फिर से शुरू करने की धमकी दी थी।

बांग्लादेश में नरसंहार के लिए यूनुस जिम्मेदार

नई दिल्ली। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार मोर्चा संभालते हुए, देश में अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न को लेकर देश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया है। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन में उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार करने और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की योजना बनाई गई थी। बता दें कि, मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उन्होंने 5 अगस्त को ढाका में अपने आधिकारिक आवास पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, हथियारबंद प्रदर्शनकारियों को गणभवन की ओर भेजा गया। अगर सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई होती, तो कई लोगों की जान जा सकती थी। यह 25-30 मिनट का मामला था, और मुझे वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने सुरक्षा गार्डों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गोली न चलाएं।

असम में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बिक सकेगा बीफ

नई दिल्ली। असम सरकार के मंत्रिमंडल की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें तमाम अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि असम में रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस (बीफ) नहीं बिकेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गोमांस उपभोग पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में नहीं खा पाएंगे। यह नियम सार्वजनिक समारोह में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगा। वहीं असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह गोमांस प्रतिबंध का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान जाकर बस जाए। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक और पार्टी महासचिव डॉ हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा कि कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे?

भारत ने जीता जूनियर एशिया कप का खिताब

नई दिल्ली। अराइजीत सिंह हुंडल के चार गोल की मदद से गत चैंपियन भारत ने बुधवार को पुरुष जूनियर एशिया कप के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर खिताब की हैट्रिक बनाई. यह महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारत का पांचवां खिताब है. इससे पहले भारत ने 2004, 2008, 2015 और 2023 में यह खिताब जीता था. कोविड-19 महामारी के कारण यह टूर्नामेंट 2021 में आयोजित नहीं किया गया. हुंडल ने चौथे, 18वें और 54वें मिनट में तीन पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और 47वें मिनट में मैदानी गोल दागा. भारत के लिए एक अन्य गोल दिलराज सिंह (19वें मिनट) ने किया. पाकिस्तान के लिए सूफियान खान (30वें और 39वें मिनट) ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला जबकि हन्नान शाहिद ने तीसरे मिनट में मैदानी गोल किया.

इसरो का प्रोबा-3 सोलर मिशन को इसरो ने टाला

श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसए) के प्रोबा-3 सोलर मिशन की लॉन्चिंग को तकनीकी खराबी के चलते टाल दिया है। बुधवार की शाम 4 बजकर 8 मिनट पर प्रोबा-3 मिशन को पीएसएलवी-सी59 से लॉन्च किया जाना था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसए) के महानिदेशक जोसेफ एशबैकर ने कहा कि गड़बड़ी कोरोनाग्राफ सैटेलाइट के प्रणोदन प्रणाली (प्रोपल्शन सिस्टम) में हुई है। यह उपग्रह के कक्षा नियंत्रण (ऑरबिट कंट्रोल) का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में अभिविन्यास (ऑरबिटिंग) और दिशा बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। इसे बृहस्पतिवार को भारतीय समयानुसार शाम 4.12 बजे फिर से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में इस मिशन के दोबारा लॉन्च की जानकारी दी है। प्रोबा-3, यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसओ) के प्रोबा सीरीज का तीसरा सोलर मिशन है। खास बात ये है कि प्रोबा सीरीज के पहले मिशन को भी इसरो ने ही 2001 में लॉन्च किया था। प्रोबा-3 मिशन के लिए स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड की टीमों ने काम किया है। इस पर करीब 20 करोड़ यूरो (करीब 1,778 करोड़ रुपये) का खर्च आया है।

संसद की डायरी

संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, किसानों को लेकर विपक्ष का हंगामा

शीतकालीन सत्र के आठवें दिन बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही फिर से शुरू हुई। दोनों सदनों में आज सामान्य रूप से कामकाज हुआ। हालांकि, विपक्ष का कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बॉयलर अधिनियम, 1923 को बदलने के लिए राज्यसभा में बॉयलर विधेयक, 2024 पेश किया। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अपेक्षाकृत सुचारु कार्यवाही देखने को मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एलएसी पर हुई सेनाओं की वापसी पर राज्यसभा को जानकारी दी और कहा कि भारत-चीन संबंधों में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने बताया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विपक्षी सांसदों ने अदाणी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

लोकसभा की कार्यवाही

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि देश में हर रेल यात्री को यात्रा टिकट पर 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56,993 करोड़ रुपये की राशि खर्च करता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1989 के रेलवे अधिनियम के साथ 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करने के प्रावधान वाला एक विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया और कहा कि इसके पारित होने से रेलवे की क्षमता में इजाफा होगा। वैष्णव ने 'रेल संशोधन विधेयक, 2024' को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में केंद्र सरकार के मंत्रियों से कहा

कि वे उन सदस्यों की बातों का जवाब देने की आदत छोड़ दें जिन्हें बोलने की अनुमति आसन से नहीं मिली है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब लोकसभा में प्रश्काल के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के कई घटक दलों के सांसदों द्वारा अदाणी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने की पृष्ठभूमि में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि सदस्यों को संसद के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। बिरला ने सदन में कहा, ''मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था, फिर आज आग्रह कर रहा हूं..... संसद भवन के प्रवेश द्वार पर अवरोध होने की शिकायत कई सदस्यों ने की है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि संसद भवन में आगमन के समय प्रवेश द्वार को अवरुद्ध नहीं करें।''

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और एक हिंदू पुजारी को गिरफ्तार करने का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाते हुए हेमा मालिनी समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ सदस्यों ने पड़ोसी देश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया और संसद से एक प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर और इस्कॉन संस्था एवं उसके अनुयायियों पर चरमपंथियों द्वारा किए जा रहे हमले निंदनीय हैं।

स्वास्थ्य बीमा के तहत 'क्लेम' की गई पूरी राशि का लाभ पॉलिसी धारकों को नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को सरकार से अनुरोध किया कि इस ओर ध्यान दिया जाए और मध्यम वर्ग का संरक्षण किया जाए।

राज्यसभा की कार्यवाही

कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों और विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने के वादे को पूरा नहीं करने के विरोध में बुधवार को राज्यसभा से बहिर्गमन किया। इससे पहले, सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत दिन के सूचिबद्ध कामकाज को निलंबित करने की मांग करने वाले नोटिस को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने बुधवार को बताया कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों में धोखाधड़ी और कुप्रबंधन रोकने के लिए तथा इन समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पाल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए उठाए गए कदमों में समवर्ती ऑडिट का प्रावधान शामिल है, ताकि गड़बड़ी तुरंत संज्ञान में आए। पहले यह ऑडिट साल में एक बार होता था।

भारत ने सीमा मुद्दे के निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए चीन से संपर्क बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए बुधवार को कहा कि सतत कूटनीतिक साझेदारी को दर्शाने वाले हालिया घटनाक्रम ने दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के संबंध वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की मर्यादा का सख्ती से सम्मान करने और समझौतों का पालन करने पर निर्भर होंगे।

मृत माता-पिता से उपसरपंच ने निकाला राशन

18 महीने की गड़बड़ी की शिकायत, प्रारंभिक जांच में शिकायत

बालोद। जिले के नेवारीकला गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के उपसरपंच पर मृत मां के नाम से राशन आहरण करने का आरोप लगाया है। ग्राम समिति के लोगों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर के सामने उप सरपंच की शिकायत रखी। वहीं पूरे मामले में खाद्य विभाग ने कहा कि प्रारंभिक दृष्टिकोण में ऑनलाइन चेक करने पर राशन आहरण की बात सामने आ रही है। जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। वहीं उपसरपंच ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है।

ग्रामीणों ने लगाया 18 महीने से राशन निकालने का आरोप

ग्रामीण अध्यक्ष गणेश राम ने बताया कि ग्राम पंचायत नेवारीकला खाद्यान्न योजना में बड़ा गोल-माल चल रहा है। खुद सैल्स मैन उपसरपंच टिकेश कुमार शर्मा द्वारा अपने मृत मां और पिता के नाम से करीब 18 माह से अपने मृत माता पिता के नाम के राशन का उपयोग स्वयं उपसरपंच

टिकेश कुमार शर्मा कर रहा है। वहीं ग्रामीण समिति के सचिव मुनेश कुमार ने बताया कि भाजपा शासन राज्य में आने के बाद नया राशन कार्ड जारी किया गया है।

खुद उपसरपंच द्वारा सचिव और सरपंच से मिलकर अपने नाम से नया राशन कार्ड बना चुका है। सेल्समेन खुद ग्राम पंचायत का उपसरपंच है। बार-बार उनसे सवाल पूछने पर जानकारी न देते हुए गोलमोल जवाब दिया जाता है। जिसके कारण हम कलेक्ट्रेट से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर खाद्य सामाग्री रिकभरी व पद से हटाकर 6 वर्ष के लिए पंचायत में किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं देना बनता है। बाकी आपकी कार्यप्रणाली के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाय।

खाद्य विभाग ने तुरंत की जांच - दो सदस्यीय बनेगी टीम

मामला जब खाद्य विभाग पहुंचा तो जिला अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी जिसके बाद परिणाम चौंकाने वाले रहे उपसरपंच टिकेश शर्मा की स्वर्गवासी मां और पिता के नाम से बने राशन कार्ड से राशन निकाले जाने की बात सामने आई है लेकिन उनके परिवार से किसी के राशन निकलने की बात कही है जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि पूरे मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो सदस्य टीम बनाई जाएगी जिसमें खाद्य विभाग और जनपद के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहेंगे उन्होंने जांच के बाद ही मामले का स्पष्टीकरण होने की बात की है।

उप सरपंच ने बताया षडयंत्र

गांव के उप सरपंच टिकेश शर्मा ने पूरे मामले को षडयंत्र बताया है उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद परिवार सहायता राशि मिलने की उम्मीद में मैं किसी का नाम नहीं कटवाया था इसी दौरान मां की भी मृत्यु हो गई उन्होंने कहा कि 3 महीने से मेरा राशन कार्ड नवीनीकरण हो गया है और मैं राशन नहीं निकल रहा हूं वहीं उन्होंने एक गंभीर मामले का खुलासा किया कि गांव में कई से लोग हैं जो अमृत व्यक्तियों के नाम से राशन कार्ड का आहरण कर रहे हैं अगर जांच होती है तो सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

कोरिया के 13 गांवों में पहुंचा साफ पानी, हजारों परिवारों को मिली राहत

कोरिया। पानी, जो जीवन का आधार है, उसकी कमी से जूझते ग्रामीण अब राहत की सांस ले रहे हैं। राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना ने कोरिया जिले के सैकड़ों घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर न केवल जीवन को सरल बनाया है, बल्कि ग्रामीणों की दिनचर्या में बड़ा बदलाव भी लाया है।

सोनहत विकासखंड के पोड़ी ग्राम पंचायत के श्रीमती सुंदरी के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं। पहले उन्हें दूरदराज के कुओं और तालाबों से पानी लाना पड़ता था, जिससे न केवल समय, बल्कि मेहनत भी बहुत लगती थी। लेकिन अब घर में लगे नल से साफ पानी मिलने से उनकी जिंदगी आसान हो गई है। वे कहती हैं, अब मुझे बच्चे को छोड़कर पानी लाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। यह सरकार का बड़ा उपहार है।

ग्राम कछवाखोह के मानसिंह बताते हैं कि उनके लिए घर में नल लगने का सपना कभी हकीकत नहीं लग रहा था। पानी की किल्लत और आपसी झगड़ों ने उनके जीवन को कठिन बना रखा था। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत उनके घर तक नल कनेक्शन पहुंचा, और अब पानी की किचकिच से छुटकारा मिल गया है। मानसिंह भावुक होकर कहते हैं, यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं।

13 गांवों में 1477 घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है और हजारों ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी की सुविधा मिल रही है।

कलेक्टर द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है जहाँ खामियां है, उसे दूर किया जा रहा है और जिले के अन्य गांवों व घरों में भी शीघ्र नल कनेक्शन व पानी मिले इस पर कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में न केवल पानी की समस्या का समाधान किया है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया है। इस पहल के लिए कोरिया जिले के ग्रामीण प्रशासन और अधिकारियों को जनता की ओर से धन्यवाद मिल रहा है।

यह योजना न केवल जल संकट से राहत दिला रही है, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और समय की बचत जैसे कई आयामों में ग्रामीणों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। इन गांवों के लोग अब गर्व से कह सकते हैं, हर घर नल, हर घर जल।

मंडराते हाथियों की परवाह किए बगैर ग्रामीणों ने गड्ढे में फंसे हाथी के शावक को बचाया

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों के दल में से एक हाथी शावक खेत में बने तालाब नुमा गड्ढे में गिर गया। शावक ने काफी देर तक खुद को गड्ढे से निकालने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। बताया जा रहा है कि शावक झुंड के साथ पानी पीने गड्ढे के पास पहुंचा था और कीचड़ होने के कारण फिसल गया।

रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा और लैलूंगा सीमा के चिल्कागुढ़ा की घटना है। यहां खेत में पानी से भरे गड्ढे में 41 हाथी का दल सोमवार सुबह 7 बजे के आसपास नहाने और पानी पीने गया था। कुछ देर बाद सभी हाथी गड्ढे से निकल गए लेकिन एक शावक उसी में फंस गया। इधर शावक के गड्ढे में फंसे होने के कारण हाथियों की चिंघाड़ से पूरा जंगल गूंजने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने हाथी के शावक को पानी से भरे गड्ढे में देखा।

ग्रामीणों ने लैलूंगा एसडीओ और घरघोड़ा एसडीओ समेत वन अमले को इस घटना के बारे में तुरंत जानकारी दी। वन विभाग की टीम के आने से पहले ही ग्रामीणों ने हाथी शावक का रेस्क्यू शुरू किया। फावड़े की मदद से गड्ढे के किनारे की मिट्टी पाटकर शावक के बाहर आने के लिए रास्ता बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय वे गड्ढे में फंसे हाथी शावक को निकालने का प्रयास कर रहे थे उस दौरान हाथियों का दल आसपास ही मौजूद था। पूरा क्षेत्र हाथियों के चिंघाड़ से गूंजता रहा। लेकिन गांव के ग्रामीण हाथी शावक की जान बचाने जुटे रहे और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। ग्रामीणों के हाथियों के बचाने का वीडियो भी सामने आया है।

घरघोड़ा एसडीओ केपी डिंडोरे ने बताया घरघोड़ा और लैलूंगा रेंज की यह घटना है। किसान पानी रखने के लिये खेत में गड्ढा खोदकर रखे रहते हैं। उसमें हाथी का शावक गिर गया था। शावक के रेस्क्यू के दौरान 41 हाथियों का दल मौजूद था। जिस समय ग्रामीणों ने हाथी शावक का रेस्क्यू किया उस समय दोनों रेंज के एसडीओ मौजूद थे। हाथी शावक का सफलता पूर्वक रेस्क्यू करके निकाल लिया गया।

जानकारी के मुताबिक इन दिनों रायगढ़ जिले के जंगलों में कुल 99 जंगली हाथी अलग-अलग दल में अलग-अलग रेंज में घूम रहे हैं। हाथियों के इस दल में नर हाथी 27, मादा हाथी 49 के अलावा 23 हाथी शावक शामिल हैं। हाथियों के दल मे सर्वाधिक हाथी की बात करें तो लैलूंगा रेंज में 41 हाथी, धरमजयगढ़ के सेमीपाली में 20 हाथी, कापू रेंज के रतनपुर 20 हाथी घूम रहे हैं।

नारायणपुर के दो प्रगतिशील कृषक को मिला मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स

नारायणपुर। कृषि जागरण एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रगतिशील कृषकों को प्रोत्साहन करने हेतु सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर के दो प्रगतिशील कृषक ग्राम बांगडोंगरी के चौतू राम यादव एवं बेलगांव के नीलकंठ नाग को मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 से 3 दिसंबर को सम्मानित किया गया।

कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग से दोनों किसान अपने-अपने परिस्थिति में समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर अपने आय के साधन को बढ़ाया है। चौतू राम यादव खरीफ में धान के साथ देशी मुर्गी पालन करते थे जो वर्तमान में खरीफ के साथ रबी सीजन में चना, मटर, मक्का के साथ-साथ मछली पालन, गाय पालन, मुर्गी प्रजनन इकाई एवं केंचुआ खाद उत्पादन कर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और नीलकंठ नाग खरीफ में धान एवं रबी में कैप्सिकम एवं अन्य सब्जी के साथ मछली सह बतख एवं मुर्गी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं।

आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती मामला

फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज

गरियाबंद। देवभोग के लाटापारा स्थित पूंजीपारा आंगनबाड़ी में चर्चित सहायिका भर्ती के मामले में पुलिस ने नियुक्ति हासिल करने वाली अभ्यर्थी तारेणी बघेल समेत अन्य के खिलाफ देवभोग पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(3), 338, 336(3) और 340(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने बताया कि मामले में ग्रामीण मधु यादव ने लिखित शिकायत दी थी, जिसकी प्राथमिक जांच में तारेणी बघेल द्वारा 8वीं के अंकसूची में छेड़ छाड़ कर प्रस्तुत करने की पुष्टि हुई थी। फिलहाल मामले नामजद अभ्यर्थी की आरोपी बनाया गया है। जांच में जिसकी भी संलिप्तता पाई जायेगी उन्हें इन्हीं अपराध के तहत आरोपी बनाया जाएगा।

तारेणी बघेल बाड़ीगांव मिडिल स्कूल में कक्षा 8 वीं पास किया था, जब इसी गांव के हाई स्कूल में 9 कक्षा पढ़ने गई थी तो उसके द्वारा हाई स्कूल में 81.26 प्रतिशत अंक वाले मार्कशीट दिया था। जबकि नौकरी में भर्ती के लिए 85.01 प्रतिशत अंक वाले मार्कशीट दिया गया। तारेणी द्वारा नियुक्ति के लिए भरे गए आवेदन फार्म में भी अंकों से छेड़ छाड़ किया गया था।

मामले में चयन समिति व दोबारा कूट रचित अंक सूची जारी करने वाले प्रधान पाठक भी जांच के दायरे में हैं। इन सभी जवाबदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच आगे बढ़ी तो इन पर भी जल्द पुलिस कानूनी शिकंजा कसेगी।

अवैध खनन पर 10 वाहन राजसात

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के रतनपुर क्षेत्र के जंगल में जारी अवैध खनन पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को राजसात कर लिया है। इनमें हाइवा, पोकलेन और ट्रैक्टर शामिल हैं। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश के तहत यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस कार्रवाई में किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वाहनों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर को रतनपुर वन परिक्षेत्र के धोबघाट में अरपा नदी के किनारे गश्त कर रही टीम को अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना मिली। जिसके बाद बिलासपुर वन मंडल की टीम ने प्रशिक्षु आईएफएस और प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर टीम ने छापा मारा और मौके पर पोकलेन से खुदाई और हाइवा से रेत परिवहन करते वाहन पाए गए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सचिव ने मांगी रिश्वत, सस्पेंड

कबीरधाम। बुधवार को कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जनपद पंचायत पंडरिया के ग्राम पंचायत कोयलारीकापा के सचिव मालिकराम गोयल को सस्पेंड कर दिया है। सचिव पर आरोप है कि उसने एक ग्रामीण से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी है। जांच के बाद कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। जारी आदेश में बताया गया हैं कि सचिव मालिक राम गोयल के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए राशि की मांग करने और अभद्र व्यवहार करने के कारण निलंबन के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। सचिव मालिकराम गोयल द्वारा अपने कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 में निहित प्रावधानों के विपरित है व कदाचरण की श्रेणी में आता है। सचिव मालिकराम गोयल को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 में निहित प्रावधान अनुसार सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड अवधि में गोयल का मुख्यालय जनपद पंचायत पंडरिया रहेगा व नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

शादी में खाने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से किया हमला

दुर्ग। दुर्ग के जेवरा सिरसा में शादी समारोह में खाना के दौरान विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक घर में शादी की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान एक युवक का खाना परोस रहे दो नाबालिगों के साथ खाने की चीजों को लेकर विवाद हुआ। उस समय तो विवाद लोगों ने मिलकर शांत करा दिया। लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो दोनों नाबालिगों के साथ फिर से युवक ने विवाद किया। विवाद के दौरान चाकू से वार कर दिए घायल नाबालिग लड़के को अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। जेवरा सिरसा में मंगलवार रात एक शादी हो रही थी। इसी शादी में खाने का कार्यक्रम था। शादी में शामिल होने के लिए एक युवक आया। जहां उसने खाने को लेकर वहां खाना परोस रहे दो नाबालिगों से विवाद किया। जानकारी के अनुसार शादी में खाने की प्लेट में एक और रसगुल्ला नहीं देने को लेकर युवक ने आपत्ति जताई। वहीं नाबालिग उसे रसगुल्ला नहीं दे रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के बाद जब मामला शांत हुआ तो लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे।

छत्तीसगढ़ में आया भूकंप, तेज झटकों से कांपी धरती

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तेलंगाना रहा। ये झटके महाराष्ट्र तक महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके कोंटा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जगदलपुर सहित कई जगहों पर महसूस किए गए हैं। तेलंगाना के मुलूगु में भूकंप का केंद्र रहा है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई है। भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप का असर बस्तर संभाग के कई इलाकों में देखा गया। तेलंगाना में बुधवार सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि इसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, सुबह तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। हैदराबाद में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 7:27 बजे आया। इसका केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर गहराई में था।पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है।

हाथी ने कमार बच्ची को पटक-पटककर मार डाला

धमतरी। नगरी ब्लॉक के रिसगांव आमाबहार में मंगलवार रात करीब 11 बजे हाथी ने बच्ची को घर से उठाकर बाहर निकाला और पटक-पटककर मार डाला। बताया जाता हैं कि हाथी शावक है जो बीते दिनों पोटाश बम की चपेट में आकर घायल हुआ था, उसकी हालत चिंताजनक हुई, तो जंगल सफारी के डॉक्टरों ने इलाज किया। कैंप लगाकर 24 घंटे निगरानी की। शावक की जान बचाने हरसंभव प्रयास किया तब जाकर उसकी जान बची। 3 नवंबर को शावक अघन रिसगांव रेंज में मौजूद थे। देर रात हाथी जंगल की ओर चला गया और आक्रमक होकर वन विभाग के कर्मचारियों को भी खदेड़ा। जैसे-तैसे जान बचाकर भागे। आधी रात उसने कमार बस्ती में सोई 3 साल की कमार बच्ची को कुचलकर मार डाला। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा करने के बाद शव परिजनों को सौंपने के साथ ही मुआवजा राशि भी दे दिया।

पेड़ से लटकता ग्रामीण का शव मिलने से मचा हड़कंप

कोरबा। कोरबा में उरगा थाना के तहत नवलपुर नवापारा में गांव में एक ग्रामीण की लाश पेड़ पर लटकती देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। खेत पर फसल काटने पहुंचे ग्रामीणों की नजर जब उसे पर पड़ी तब इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जहां मौके पर उरगा थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और पहचान करवाई में जुट गई। गांव के कोटवार के द्वारा आसपास गांव में मुनादी कराई गई वही व्हाट्सएप के द्वारा फोटो ग्रुप में वायरल किया गया जहां काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण की पहचान 35 वर्षीय मोहन सिंह बिंझवार के रूप में की गई। इसकी सूचना तत्काल परिजनों को दी गई जहां शव की पहचान कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज शव रवाना किया गया। मृतक के परिजन सजन लाल ने बताया कि उसे फोन पर जानकारी मिली की मनमोहन पिछले तीन दिनों से लापता है उसकी खोज भी आसपास गांव और रिश्तेदारों के घर की गई लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

धान का अवैध परिवहन, भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई

■ 118 क्विंटल धान जब्त

बस्तर। छत्तीसगढ़ सहित पूरे बस्तर में 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो गई है। धान खरीदी के शुरू होते ही अवैध धान तस्कर भी सक्रिय हो गये हैं। अवैध धान केंद्र न पहुंचे इसके लिए आवश्यक टीम जांच और चेकिंग में जुट गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने मंगलवार को अवैध धान परिवहन करते, अवैध धान विक्रय करते और अवैध धान भंडारण करते 118 क्विंटल धान जब्त किया है।

एसडीएम भरत कौशिक ने बताया कि वर्तमान में बस्तर में धान खरीदी जोरों पर है। कोचियों और बिचौलियों के जरिये सीमावर्ती राज्यों और जिलों से अवैध धान

बस्तर न पहुंचे इसके लिए चेक पोस्ट और उड़नदस्ता की टीम गाड़ियों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसी दौरान मंगलवार को ओडिशा से बस्तर आ रही गाड़ी को बॉर्डर के पास मार्केल में रोका गया। जांच के दौरान गाड़ी में 210 पैकेट धान लोडिंग था। जिसका वजन 84 क्विंटल पाया गया। धान को जब्त कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है।

एसडीएम ने बताया कि धान उपार्जन केंद्र में अवैध धान बिक्री करने के उद्देश्य से भंडारण किये गए 26 क्विंटल धान को तहसीलदार ने जब्त किया। इसके अलावा देवड़ा में बिना मंडी शुल्क जमा किये भंडारण किये गए 8 क्विंटल धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

हर साल खरीदी के दौरान बिचौलियों पड़ोसी राज्यों से अवैध धान परिवहन करके बस्तर पहुंचाते हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रभारियों से सांठगांठ करके धान का विक्रय किया जाता है। जिसे रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में बस्तर जिला प्रशासन की टीम के साथ ही पुलिस बल भी तैनात रहता है।

तेज रफ्तार इनोवा डिवाइडर से टकराई, पलटने से छह लोग घायल

कोरबा। जिले के पाली थाना क्षेत्र में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई। घटना पाली थाना अंतर्गत ग्राम मुनगाडीह नेशनल हाईवे मार्ग पर घटी। जहां एक तेज रफ्तार इनोवा कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।

इस घटना में कार में सवार छह लोग घायल हो गए हैं। जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और इसकी सूचना पाली पुलिस और 112 को दी गई।

हादसे की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने कार में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद रेस्क्यू कर घंटों की मशक्कत कर बाहर निकाला। सभी घायलों को पाली स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि इनोवा कार में सवार लोग भिलाई निवासी थे, जो बनारस से वापस भिलाई लौट रहे थे। इसी दौरान रात लगभग दो बजे दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार हादसे का कारण बना है। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद घटना घटी और वाहन दो बार सड़क पर अनियंत्रित होकर पलटा। घटना के बाद वाहन में चीखपुकार मचाने लगे। किसी तरह दो लोग पहले बाहर आये और वाहन के फंसे लोगों को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया।

इसके बाद 112 और पाली पुलिस ने किसी तरह सभी को बाहर निकाला और पाली उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया। जहां उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे और एक युवक की हालत गम्भीर है। उसे रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है इनोवा सवार भिलाई के रहने वाले हैं। पारिवारिक कार्यक्रम से बनारस कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। वापस लौटते समय यह घटना घटी है।

सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कार और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, सभी एयरबैग खुलने के बाद भी किसी की भी जान नहीं बच पाई। वहीं पिकअप के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। घटना सूरजपुर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। गौरतलब है कि प्रतापपुर-अंबिकापुर मार्ग पर मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे गोटगवां के पास कार और पिकप में जबरदस्त हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गोवर्धनपुर गांव से चार युवक कार क्रमांक सीजी 29 एई 7704 में सवार होकर अंबिकापुर जा रहे थे। वहीं, कुछ लोग गोटगवां के पास टमाटर लोडकर पिकअप क्रमांक यूपी 64 एटी 380 से बनारस जा रहे थे। कार और पिकअप की आमने-सामने से इतनी जोरदार भिड़ंत हुई कि हादसे के बाद कार के चारों एयर बैग खुल गए थे।

प्रदेश में हर गरीब के पक्के मकान का सपना होगा साकार: मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन के आधार पर मिली नए आवासों की स्वीकृति

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के

त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल ने ननि और पालिका अधिनियम में संशोधन अधिनियम पर लगाई मुहर

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कैबिनेट की सिफारिश पर नगर निगम और पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश पर मुहर लगा दी है और इसका राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसमें करीब एक दर्जन से अधिक धाराओं में संशोधन किया गया है। इनमें नगर निगम अधिनियम की धारा 5,9,11, 11-क, 14, 14-क, ख, ग, 15, 16, 17, 17-ख, 18,20,23-क, 24,422,441 में बदलाव किया गया है। और पालिका अधिनियम की धारा 3, 19,20, 20-क ख,32,32-क ख ग,33,34,35,43, 43-क 47,55,56,62,63,328 बदल दिए गए हैं। इनके मुताबिक अब महापौर और पालिका अध्यक्षों के चुनाव आम मतदाता करेंगे। इस अधिसूचना के बाद नगरीय प्रशासन विभाग जल्द ही पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकालेगा। अगले सप्ताह इन चुनावों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं आयुक्त अजय सिंह ने चुनाव के दौरान सुरक्षा को को लेकर राज्य स्तरीय बैठक कर चुके हैं।

जिला स्तर युवा उत्सव का आयोजन 6 को सभी विकासखण्ड पर होगा

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस भी युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 6 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक होगा जो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आरंग, अभनपुर, तिल्दा, धरसींवा में किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 15 से 29 वर्ष के युवा शामिल हो सकते हैं। युवा उत्सव में लोकनृत्य सामूहिक, लोकगीत सामूहिक, लोकर्नतय व्यक्तिगत, लोकगीत व्यक्तिगत, कहानी लेखन, चित्रकला, वक्तृत्व कला या तत्कालिक भाषण कविता, विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाईल, कृषि उत्पाद, तथा रोकबैंड भी इत्यादि विघा शामिल होगें। राक बैंड सिर्फ जिला और राज्य स्तर पर होगा। यह 06 दिसम्बर को अभनपुर विकासखंड में दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल अभनुपर, धरसींवा में इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम परसतराई आरंग में आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, तिल्दा मे मीडिल स्कूल ग्रांउड तुलसी नेवरा में होगा।

नया रायपुर से मंदिर हसौद तक शीघ्र पटरियों पर होगी मेमू

रायपुर। नया रायपुर से मंदिर हसौद के बीच मंगलवार की शाम को रेलवे द्वारा एमप्टी मेमू रैक (खाली ट्रेन) का ट्रायल रन किया गया, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नया रायपुर और मंदिर हसौद के मध्य जल्द ही मेमू ट्रैक पर दौडने लगेगी और आगे सबकुछ योजनाबद्ध हुआ तो मेमू को रायपुर रेलवे स्टेशन तक भी लाया जा सकता हैं। हालांकि इस बात की अधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। उल्लेखनीय हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में बने सीबीडी स्टेशन का उद्घाटन नवंबर में किया है। उद्घाटन के बाद आवश्यक उपकरणों और सुविधाओं से सीबीडी को लैस करने की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है जिससे संकेत हैं कि अगले सप्ताह तक नया रायपुर से मंदिर हसौद के बीच मेमू ट्रेन दौडनी शुरु हो जाएगी।

एक पेड़ मां के नाम पर राज्यपाल डेका ने रूद्राक्ष पौधा रोपण किया

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज धमतरी प्रवास के दौरान जिला पंचायत परिषद में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रूद्राक्ष का पौधा रोपण किया एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की।

शगुन फार्म हाउस से कर्मचारी ने दोस्त के साथ मिलकर किया टोयटा पार, गिरफ्तार

रायपुर। वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म हाउस की पार्किंग से टोयोटो कार चोरी करने के मामले में पुलिस ने वहीं के कार पार्किंग चालक और नारकोटिक एक्ट एवं मारपीट के प्रकरण में जेल जा चुके उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की टोयटा कैमरी कार सी जी/04/एम एम/6000 भी जब्त कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोमांस्क्यु विला लाभाण्डी निवासी आशीष जैन मैग्नेटो माल में एक कंपनी का संचालक है। उसमे अपनी कंपनी के नाम से पिछले सप्ताह 29 तारीख को एक काले रंग की टोयटा कैमरी कार सी जी/04/एम एम/6000 को 54 लाख में खरीदा था और 30 नवंबर की रात शगुन फार्म हाउस बर्थ-डे पार्टी में गया था। आशीष रात्रि करीब 02.30 बजे बर्थ-डे पार्टी से बाहर निकला और वैलेट पार्किंग को दिये गये पर्ची को वापस देकर अपनी कार को लाने के लिए बोला तो वैलेट पार्किंग ड्राइवर ने कार को पार्किंग में नहीं होना बताया। दोनों ने कार को ढूंढ़ा पर कार नहीं मिली। आशीष तेलीबांधा थाने आकर धारा 303 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध दर्ज कराया। पुलिस ने फार्म हाउस और बाहर रोड पर लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों चेक किए। इसमें टिकरापारा रायपुर निवासी अब्दुल शहबाज एवं आकाश कुमार गुप्ता और एक अन्य कार ले जाते नजर आए। इनमें एक वहीं कार पार्किंग चालक निकला जिसे पुलिस गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया।

नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा: उद्योग मंत्री देवांगन

निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का उद्योग मंत्री ने किया शुभारंभ

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर आधारित निर्यात प्रोत्साहन एवं निवेश हेतु स्टेकहोल्डर कनेक्ट कार्यशाला का शुभारंभ किया। नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेस कुमार सहित उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हम सब राज्य के औद्योगिक विकास एवं राज्य से निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए यहां एकत्रित हुए है। प्रदेश में नवीन उद्योग नीति 2024-2030 जो एक नवंबर से लागू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे स्थापित हो इसे ध्यान में रखकर यह उद्योग नीति तैयार की गई है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित केबिनेट बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

इस नीति में ज्यादा से ज्यादा अनुदान सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो इसमें प्रावधान किए गए है। उद्योग धंधे स्थापित होने से प्रदेश का विकास होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्यामियों की सुविधा के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली लागू किया गया है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित होने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। श्री देवांगन ने कहा कि उद्योगों के साथ-साथ इससे अप्रत्यक्ष रूप से हजारो लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत सिंह ने कहा कि कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति अन्य राज्यों के लिए उदाहरण साबित होगी। सिंगल विंडो प्रणाली से उद्यामियों को सहुलियत होगी। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि नीति आयोग की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सचिव उद्योग श्री रजत कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छुट, विद्युत शुल्क छुट, प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान के प्रावधान किए गए है। सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेस कुमार ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान सवाल-जवाब के दौरान जिज्ञासा का समाधान किया गया।

टामन सोनवानी संपत्ति मामला

भूपेश और कांग्रेस के संरक्षण में भ्रष्टाचारियों की ऐश थी: रोहरा

रायपुर। पीएससी घोटाले में गिरफ्तार पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामनसिंह सोनवानी की काली कमाई, रिसोर्ट, जमीन समेत अवैध सम्पत्तियों के ताजा खुलासे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। रोहरा ने कहा कि सोनवानी की काली कमाई के खुलासे से यह फिर साफ हुआ है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल का हर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण रहा और हर भ्रष्टाचारी के वकील तक बनकर बघेल जाँच एजेंसियों के खिलाफ रोना-धोना मचाने में पीछे नहीं रहे और आज भी डरे-सहमे बघेल वही सब कर रहे हैं।

रोहरा ने कहा कि टामन सोनवानी की प्रॉपर्टी से जुड़ी उसके फार्म हाउस, उसकी जमीनों से जुड़े एक समाचार पत्र में हुआ खुलासा यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस के सत्तावादी और राजनीतिक संरक्षण में अफसरों ने किस कदर छत्तीसगढ़ को लूटा-खसोटा! तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करते रहे और छत्तीसगढ़ महतारी का खजाना लूटने वालों के सहभागी बने हुए थे। श्री रोहरा ने कहा कि नौकरशाहों ने जनता का पैसा लूटकर निजी संपत्तियां बनाने में ध्यान केंद्रित कर रखा था, और कहीं-न-कहीं उसमें शायद कांग्रेस सरकार का भी हिस्सा था। इसीलिए यह सारा भ्रष्टाचार होते समय कांग्रेस सरकार ने अपनी आँखें बंद कर ली थीं। श्री रोहरा ने कहा कि पीएससी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए केवल एक अभ्यर्थी ही नहीं, वरन उसका पूरा परिवार मेहनत करता है, मां-बाप कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और, पिछले कांग्रेस शासनकाल में उन्हीं युवाओं के साथ सरेआम खिलवाड़ किया गया।

उन्होंने कहा कि अब युवाओं के भविष्य को सँवारने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, वह खुद अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य सँवारने में लगा था! यह प्रदेश की प्रतिभासम्पन्न युवा पीढ़ी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई। भाजपा ने इस पर केवल चिंता ही नहीं जताई अपितु पीएससी घोटाले की सीबीआई जाँच का वादा किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के सुशासन ने आज ऐसे घोटालेबाजों के लिए जेल में स्थान रखा हुआ है। भाजपा बार-बार जो आरोप लगाती थी कि पीएससी में घोटाला हुआ है, टामन सोनवानी बहुत ही भ्रष्ट नौकरशाह था, अब यह बात बार-बार अलग-अलग तथ्यों से साबित हो रहा है। श्री रोहरा ने कहा कि महज एक छोटे-से कार्यकाल में कई एकड़ की जमीनों को खरीद लेना, रिसोर्ट बना लेना, इस बात का फिर से प्रमाण है कि कांग्रेस के सत्तावादी व राजनीतिक संरक्षण में नौकरशाहों ने भी छत्तीसगढ़ की जनता का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए साक्षात्कार 17 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक की पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार 17 दिसंबर को होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर वर्गवार और उपवर्गवार 45 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार दो पालियों में होगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह 10 बजे और द्वितीय पाली दोपहर दो बजे से आयोजित होगी।

साक्षात्कार से एक दिन पहले 16 दिसंबर को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन दो पालियों में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे प्रथम पाली और दोपहर डेढ़ बजे द्वितीय पाली आयोग कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने वाले या अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन उप निरीक्षक के कुल 15 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम तीन अक्टूबर को घोषित किया गया। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नि:शक्तजन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पहचान पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र मूल प्रति और स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

एम्स, डीकेएस और मेकाहारा अस्पताल पहुँचे राजस्व मंत्री वर्मा

■ मरीजों का पूछा हाल

रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा आज सुबह राजधानी रायपुर स्थित एम्स, डी के एस और मेकाहारा हॉस्पिटल पहुँचे। इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ-साथ मरीज़ों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री वर्मा ने अस्पताल की व्यवस्था और इलाज के संबंध में मरीजों से जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान अस्पताल के उपस्थित चिकित्सकों को समय पर मरीज़ों को बेहतर इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने बालौदाबाज़ार जिले के ग्राम रवान के रहने वाले श्री पुकार यादव, ग्राम देवरी की श्रीमती निर्मला वर्मा, बालौदाबाज़ार के श्री सुमन दास साहू से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। सिर में चोट के इलाज के लिए डी के एस के वार्ड- सी 6 में भर्ती 20 वर्ष के श्री पुकार सिंह ने बेहतर इलाज के कारण स्वास्थ्य में तेजी से सुधार की जानकारी दी। इसी तरह नस में ब्लाकेज के इलाज के लिए मेकाहारा हॉस्पिटल के वार्ड-19 में भर्ती 55 वर्षीय श्री सुमन दास साहू ने स्वास्थ्य में सुधार की बात कही। इसी तरह बलौदाबाजार के ग्राम देवरी की 54 वर्षीय श्रीमती निर्मला वर्मा निमोनिया के इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। श्री वर्मा ने उनके स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से चर्चा कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए केन्द्रीकृत परीक्षा का आयोजन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सत्र 2024-25 में कक्षा 5वीं और 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री साय ने यह कदम विद्यार्थियों की शिक्षा स्तर को सुधारने और शैक्षणिक वातावरण को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया है। यह परीक्षा राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में संचालित होगी। हालांकि सीबीएससी और आईसीएससी पाठ्यक्रम वाले विद्यालय इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन नवा रायपुर से समस्त जिला कलेक्टर और जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी कर दी गई है।

स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कहा कि परीक्षाएं जिला स्तर पर निशुल्क आयोजित की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारी गोपनीयता बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएंगे। परीक्षा मार्च माह में आयोजित होगी और इसकी समय-सारणी लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को पूर्ण गोपनीयता के साथ तैयार किए जाएंगे और प्रश्न पत्र वितरण के बाद, उन्हें संबंधित केंद्र के निकटवर्ती थाने में सुरक्षित रखा जाएगा। शिक्षकों को प्रश्न पत्र के नमूने पहले से उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि छात्रों को सही दिशा में तैयारी करा सकें।

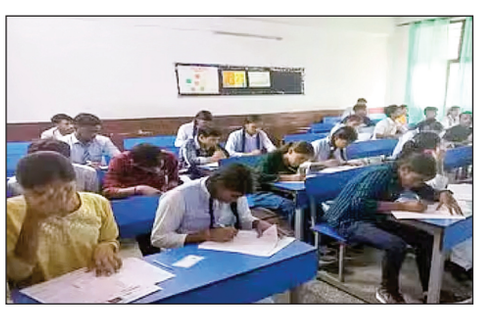

सचिव परदेशी ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय मूल्यांकन केंद्रों में किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य उन्हीं शिक्षकों से कराया जाएगा, जो कक्षा 5वीं और 8वीं पढ़ाते हैं। कक्षा चौथी और सातवीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य विद्यालयों में कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों को किसी विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, उन्हें दो महीने के भीतर पूरक परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश (छठवीं और नवमीं) दे दिया जाएगा। विद्यार्थियों की तैयारी सत्र प्रारंभ से ही सुनिश्चित किया जाएगा। केन्द्रीकृत परीक्षा की तैयारी के लिए संकुल समन्वयकों और प्रधान पाठकों की बैठक आयोजित की जाएगी।

'छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग' धमतरी वनमंडल धमतरी काष्ठागार धमतरी का ई-ऑक्सन का संक्षिप्त विज्ञापन

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि धमतरी वनमंडल धमतरी के अन्तर्गत धमतरी काष्ठागार में संग्रहित ईमारती काष्ठ, जलाऊ एवं बल्ली का ई-ऑक्सन द्वारा निर्वतन निम्नानुसार किया जावेगा। इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है, कि वे ई-ऑक्सन में भाग लेवें। ई-ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमंडल कार्यालय/वन काष्ठागार धमतरी से प्राप्त की जा सकती है।

नीलाम दिनांक - 09 दिसम्बर 2024
नीलाम समय - प्रात: 9.00 बजे से

नीलाम में प्रस्तावित वनोपज की अनुमानित मात्रा

प्रजाति	नया वनोपज		अविक्रित वनोपज		योग वनोपज	
	लट्ठा घ.मी.	बल्ली/खूंटा नग में	लट्ठा घ.मी.	बल्ली / खूंटा नग में	लट्ठा घ.मी.	बल्ली/खूंटा नग में
1	2	3	4	5	6	7
सागौन	0.716	-	43.007	1789	43.723	1789
शीशम	-	-	0.593	-	0.593	-
हल्दू/मुण्डी	-	-	9.421	-	9.421	-
साजा	-	670	-	-	-	670
पापड़ा	1.282	50	3.298	-	4.580	50
नीलगिरी	12.002	-	-	-	12.002	-
अन्य	99.817	17784	5.294	-	105.111	17784
योग-	113.960	18504	61.613	1789	175.573	20293

जलाऊ

प्रजाति	काष्ठागार धमतरी पुराना	योग	केन्द्रीय उपभोक्ता डिपो श्यामतराई पुराना बांस	कुरूद डिपो में पुराना बांस विभिन्न साईज के टुकड़ों में (साईज 5.50 मीटर)
नीलगिरी जलाऊ चट्टा	02	02	1923 नग	1000 नग
योग-	02	02	1923 नग	1000 नग

टीप:- (1) क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व एम.एस.टी.सी. ई-कार्मस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हैं।
(2) क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई. एम.डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
(3) लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो एम.एस.टी.सी. ई- कार्मस पोर्टल में अपने आईडी से लॉगइन करके देख सकते है।
(4) ई-ऑक्सन में लॉट क्रय के पश्चात् प्रथम क्रेता को 40 सेंकड का समय प्राप्त होगा उसी लॉट में अन्य क्रेताओं द्वारा 40 सेकंड के पूर्व क्रय करने पर 30 सेकंड का समय प्राप्त होगा।
(5) ईमारती काष्ठ के लॉट क्रमांक 24DMT001T से 24DMT0210T तक नया लॉट, 24DMT0211T से 24DMT0251T तक पुराना लॉट एवं जलाऊ के लॉट क्रमांक 24DMT0001F पुराने लॉट एवं बांस के लॉट क्रमांक 24DMT0001B से 24DMT0002B तक पुराना लॉट हैं।

फोन- 07722-238371
फैक्स- 07722-236137

वनमंडलाधिकारी
धमतरी, वनमंडल धमतरी

जी-242504281/3

'इंडिया गठबंधन' में पहली दरार ममता ने लिखी पटकथा

पूनम आई. कौशिश

फूट में एकता या एकता में फूट, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इंडिया गुट ने टी.एम.सी. की ममता के साथ अपनी पहली दरार विकसित कर ली है, जो अमरीका के अडानी अभियोग मुद्दे पर संसद को बाधित करने के ऊपर एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम की पटकथा लिख रही हैं, जिससे यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि वह कांग्रेस की रबड़ स्टैंप बनने से इंकार करती हैं, चाहती हैं कि राज्य और रोजी-रोटी के मुद्दे पर संसद चले। इस दिशा में उन्होंने सोमवार को कांग्रेस पर 'अडानी पर अटकने' का आरोप लगाते हुए 'इंडिया' नेताओं की बैठक में भाग नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा, ''हम एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जो कांग्रेस की चुनावी सांझेदार नहीं है। इसलिए जब हमारे मुद्दे एजैंडे में नहीं हैं तो हम ब्लॉक की बैठक में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।'' उनकी ताकत समझ में आती है क्योंकि उन्होंने राज्य में सभी 6 उपचुनाव जीते हैं। साथ ही, अन्य दलों के सांसदों ने भी मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर यू.पी. के संभल में ड्क्षहसा, पंजाब में धान खरीद में देरी, चक्रवात फेंगल के प्रभाव और बंगलादेश में इस्कॉन भिक्षुओं पर हमले जैसे जरूरी मामलों पर बहस का आह्वान किया है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में उसके निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पवार की पार्टी एन.सी.पी. में यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि राहुल बेपरवाह और अति आत्मविश्वासी हैं क्योंकि उन्होंने राज्य में केवल 6 रैलियां कीं। इसके अलावा, झारखंड में उन्होंने झामुमो की जीत का समर्थन किया। वह इस भ्रामक धारणा में खुश हैं कि कांग्रेस की लगभग 250 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर ड्क्षहदुत्व ब्रिगेड से लड़ाई है, इसलिए इसके बिना कोई भी भाजपा विरोधी लामबंदी संभव नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का अप्रभावी होना भाजपा के प्रमुख फायदों में से एक है। यह किसी भी क्षेत्रीय क्षत्रप की अखिल भारतीय भूमिका निभाने में असमर्थता से पूरित है क्योंकि कई राज्यों में वे कांग्रेस से लड़ते हुए बड़े हुए हैं और इसके राज्य स्तरीय नेता क्षेत्रीय दलों को किसी भी भाजपा विरोधी गठबंधन में सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि पराजित होने वाले प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखते हैं। एक ऐसा ही मामला दिल्ली है, जहां आगामी विधानसभा चुनावों में 'आप' और कांग्रेस एक-दूसरे से लड़ रही हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, जहां राकांपा और शिवसेना (यू) दोनों विभाजन के कारण कमजोर हो गईं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नखरों के आगे झुकने से इंकार कर दिया। यू.पी. में समाजवादी पार्ट्री ने कड़ी सौदेबाजी की और सुनिश्चित किया कि सीटों के बंटवारे में उसके हित प्रबल रहें। इसके अलावा, यह समूह विरोधाभासों से ग्रस्त है। क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस एक उपयोगी सहयोगी है, लेकिन वे सावधान हैं कि इसे पुनर्जीवित न होने दें और यह फिर से विशालकाय न बने। पहले से ही इसने, विशेष रूप से ममता में नई महत्वाकांक्षाएं जगा दी हैं, जो 'खून का स्वाद' चखने के बाद जानती हैं कि भाजपा को हराया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रीय मंच पर आगे बढने के लिए 'चैंपियन बीजेपी स्लेयर' के रूप में पश्चिम बंगाल की जीत पर भरोसा है क्योंकि उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद विपक्ष की जगह खाली हो गई है। उनकी योजना दो युक्तियों पर आधारित है- एक, राज्य में सभी गैर-भाजपा खिलाडियों के बीच एक व्यापक समझ सुनिश्चित करना, जिससे वह भाजपा के लिए एकमात्र चुनौती हों। दूसरा, अपने कद के साथ-साथ अन्य क्षत्रपों के साथ संबंध बनाएं, जिससे उन्हें स्पष्ट उम्मीदवार के रूप में देखा जाए, जिनके पास गठबंधन के चेहरे के रूप में उभरने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड, नैटवर्क और विश्वसनीयता है। हालांकि, यह कहना आसान है लेकिन इस स्पष्ट प्रश्न से नहीं निपटता, जो मोदी बनाम कौन का उत्तर देने के लिए केवल एक आम स्वीकार्य नेता के माध्यम से ही हो सकता है।

ईवीएम का विरोध, संसद ठप- सुधरने वाला नहीं है विपक्ष

मृत्युंजय दीक्षित

चार जून 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में मिली मामूली बढ़त से उत्साहित कांग्रेस को इसके तुरंत बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अपने इंडी गठबंधन के साथ भारी पराजय का मुख देखना जिसके कारण ये अब गहरी निराशा व हताशा में हैं और उन्हीं हरकतों पर उतर आए हैं जो ये लोकसभा चुनावों से पहले कर रहे थे। कुछ राजनैतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे थे कि हरियाणा तथा महाराष्ट्र में भारी पराजय के बाद विपक्षी दल संसद चलाने में सहयोग करेंगे किंतु फिलहाल ऐसा होता प्रतीत नहीं होता कि संसद के शीततकालीन सत्र में कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हो सकेगा।

संसद के शीतकालीन सत्र का प्रथम सप्ताह अडाणी व संभल हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। विपक्षी दल संसद में इसलिए भी बहस नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि जब संसद में बहस होने पर वे पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं। देश की जनता कांग्रेस को अडानी, संविधान व जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार नकार रही है किंतु कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इन्हीं मुददों को लाल किताब जिसे वे संविधान की प्रति कहते हैं हाथ में लेकर बार-बार हवा में उछालते हैं। इन्हीं मुद्दों पर सदन को बाधित करते हैं।

दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के संविधान रक्षक सम्मेलन में राहुल गाँधी ने वही किताब दिखाते हुए कहा कि इसमें कहीं सावरकर का नाम नहीं है। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी का माइक बंद हो गया और आदतन राहुल गाँधी इसके लिए भी मोदी सरकार को दोष देते हुए उसे तानाशाह बताने लगे। हर समय संविधान संविधान करने वाले राहुल गाँधी से अब पूछा जाना चाहिए कि संविधान की किताब में झूठे मुद्दे उठाकर संसद ठप करने की बात कहाँ लिखी गई है।

कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लगातार मिल रही पराजय पर जब इन दलों के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए था उस समय ये ईवीएम मशीनों और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। कांग्रेस व विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न हाईकोर्ट में 42 याचिकाएं दायर कीं किंतु हर जगह उनके वकीलो को मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों के बाद विरोधी दलों का ईवीएम पर आरोप लगाने का रेडियो एक बार फिर ऑन हो गया है। लोकसभा चुनावों के पहले भी अप्रैल माह में जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई करते हुए विपक्ष के सभी आरेपों को खारिज करते हुए कहाकि हमें भी वह दिन याद है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और पूरा का पूरा बूथ लूट लिया जाता था। हम अब देश को पुन: उस युग में नहीं ले जाना चाहते हैं। 26 नवंबर 2024 को भी सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली एक याचिका पर न सिर्फ याचिकाकार्ता को कड़ी फटकार लगाई अपितु राजनैतिक दलों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आप जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

कोर्ट ने याचिकार्ता से पूछा कि यह याचिका दायर करने का शानदार विचार अपको कैसे मिला? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरोधी दलों ने अब अतिविश्वसनीय ईवीएम मशीनों के खिलाफ नफरत की दुकान खोल ली है और यही कारण है कि अब कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों के खिलाफ अभियान प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी है जिससे वह जनता में इन मशीनों के प्रति भ्रम उत्पन्न कर सके। हारे हुए दल देश में राजनैतिक अराजकता का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं। 2014 से 2024 तक राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी लगभग 47 चुनाव बुरी तरह से हारी चुकी है और अब गांधी परिवार की नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम विरोधी अभियान प्रारम्भ कर रही है। कांग्रेस की देखादेखी महाराष्ट्र की शिवसेना- उद्धव गुट व शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने भी ईवीएम के खिलाफ अभियान प्रारम्भ कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट ने तो अपने हारे हुए उम्मीदवारों से पांच प्रतिशत वीवीपैट से मिलान करवाने के लिए याचिकाएं दायर करवाने के लिए कह दिया है। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार भी चुनावों को ईवीएम से हाईजैक कराने का आरोप लगा रहे हैं।

आज वही कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है जिसकी 2004 से 2014 तक ईवीएम द्वारा चुनी गई सरकार रही। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो अभी 4 जून 2024 को 99 सीटों पर ईवीएम द्वारा विजयी होने के बाद राहुल गाँधी को शैडो पीएम बता रही थी। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर पंजाब व दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी की सरकार ईवीएम से ही बनी है यही नहीं जम्मू कश्मीर में भी आप पाटी का खाता ईवीएम से ही खुला है। झारखंड में हेमंत सोरेन व जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार ईवीएम से ही वापस आई है। अगर बीजेपी को ईवीएम हैक करवानी होती तो वह उन सभी राज्यों में भी हैक करवा सकती थी जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं । उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री क्रमश: अखिलेश यादव और बसपा नेत्री मायावती भी अब ईवीएम का खुलकर विरोध करने लग गये हैं। 4 जून 2024 को चुनाव परिणाम आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो वह यूपी की सभी 80 सीटों पर सफलता प्राप्त करके दिखाते। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में सपा नौ विधानसभा सीटों में से केवल दो सीटें ही जीत पाई उस पर सपा मुखिया बयान दे रहे हैं कि ईवीम मशीनों की वजह से ही भाजपा सात सीटें जीतने में कामयाब रही वहीं बसपा नेत्री मायावती का कहना है कि अब वह कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि सभी चुनाव धांधली से हो रहे है। स्मरणीय है कि निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2017 में ईवीएम मशीनों को हैक करके दिखाने के लिए भरपूर अवसर दिया था किंतु कोई भी विरोधी दल उस हेकाथॉन में नहीं पहुंचा था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को हैक करके दिखाने का असफल प्रयास किया था। आज जो लोग संविधान रक्षक बनने का नाटक रच रहे हैं वास्तव में वही लोग संविधान के भक्षक हैं। यह सभी लोग चाहते हैं कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कि मुस्लिम महिला का बुर्का उठाकर उसकी पहचान न की जाये क्योंकि बुर्के की आड़ में इनका फर्जी वोट पड़ता है । ये लोग एक समय में मतदाता पहचान पत्र का भी विरोध करते थे और उसमें फोटो लगाने का भी विरोध किया था, यही लोग हैं जो आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने के भी विरोधी हैं। जनता द्वारा नकारा गया कांग्रेस का गांधी परिवार किसी न किसी तरह एक बार फिर सत्ता का नियंत्रण चाहता है और यही कारण है कि यह परिवार बार बार भारत की चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करने का असफल प्रयास कर रहा है।

ये देखना हास्यास्पद है कि वही राहुल गांधी और उनकी पार्टी ईवीएम विरोधी यात्रा की घोषणा कर रहे हैं जिन्होंने ईवीएम से ही वायनाड और रायबरेली का चुनाव जीता, जिनकी बहन प्रियंका गांधी ने वायनाड से उपचुनाव जीता, जिनको लोकसभा में इसी ईवीएम से 99 सीट प्राप्त हुयीं । ऐसे में राहुल एंड कंपनी से एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए क्या ईवीएम विरोधी आन्दोलन से पहले राहुल, प्रियंका और उनके बाकी सांसद/ विधायक आदि अपनी अपनी सीटों से त्यागपत्र देंगे क्योंकि ईवीएम से जीते गए चुनावों में तो घोटाला हुआ है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

गतांक से आगे...

इसी प्रकार त्रिकालदर्शी वेदव्यास जी के बनाये हुए पुराणों में भी भविष्यवर्णनेन बुद्ध भगवान् का चरित्र वर्णित है। यही क्यों पुराणों में तो अब से आगे होने वाले कल्कि अवतार का भी विस्तृत वर्णन विद्यमान है। क्या इससे यह मान लिया जाय कि पुराणों का निर्माण अभी तक हुआ ही नहीं?

वस्तुत: मूल पुराणों का पाठ करने पर ही यह बात सिद्ध हो जाती है, कि पुराणों का संकलन बुद्ध भगवान् से बहुत पूर्व हो चुका था; क्योंकि बुद्ध के चरित्र में प्राय: सर्वत्र भविष्यत-काल की क्रिया का प्रयोग दीख पड़ता है, यथा-

(क) बुद्धो नाम्नाऽजिनसुत: कीकष्टेषु भविष्यति। (श्रीमद्भागवत 1 । 3 । 24)

(ख) मायामोहोऽयमखिलांस्तान्दैत्यान्मोहयिष्यति ।। (पद्म0 सृष्टि 13 । 346) इन प्रमाणों में भविष्यति मोहयिष्यति आदि क्रियाएँ ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हैं कि पुराणों का निर्माण बुद्ध जी से पूर्व हो चुका था । यदि कोई आशंका करे कि व्यास जी ने अपने से सहस्रों वर्ष परवर्ती बुद्ध का चरित्र कैसे जान लिया ? सो इसका उत्तर यह है कि वेदव्यास जी योगी थे- इस बात से कोई भी पठित पुरुष इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि आर्य-साहित्य में जहाँ भी व्यास जी का वर्णन आया है वहीं आपको परम तपस्वी एवं योगाभ्यासनिरत कहा गया है। महाभारत में व्यास जी को इन्द्रियातीत ज्ञान-सम्पन्न कहा है यथा- प्रोवाचातीन्द्रियज्ञानो विधिना संप्रचोदित:। (आदिपर्व अध्याय 105। 8)

अर्थात्- त्रिकालज्ञ व्यास जी ने ईश्वर-प्रेरित होकर (माता सत्यवती से धृतराष्ट्र का अंधा होना तथा पाण्डु का विवर्ण होना जन्म से पूर्व ही) कहा था। जब व्यास जी योगी थे यह सिद्ध हो जाता है तो योगीजन, भूत, भविष्यत, वर्तमान कालत्रय के ज्ञाता होते हैं।

क्रमश: ...

आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं महर्षि अरविन्द के विचार

ललित गर्ग

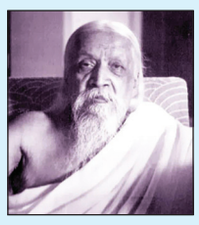

महर्षि अरविन्द एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान् स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने, नये मानव का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा में समर्पित कर दिया। उनका 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्म हुआ।

एक सार्थक प्रश्न कि क्या इंसान सामर्थ्यवान ही जन्म लेता है या उसे समाज और परिस्थितियां गढ़ती हैं? मनुष्य जीवन की उपलब्धि है चेतना, अपने अस्तित्व की पहचान। इसी आधार पर वस्तुपरकता से जीवन में आनन्द! यह बात छोटी-सी उम्र में महर्षि अरविन्द ने समझ ली थी। उनका व्यक्तित्व विरोधी युगलों से गुंथा हुआ व्यक्तित्व है। उनकी जीवन-गाथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय चेतना, दर्शन एवं अध्यात्म का एक अभिनव उन्मेष है। इतना लंबा व्यापक संघर्ष, इतना जन-जागरण का प्रयत्न, इतना पुरुषार्थ, इतना आध्यात्मिक विकास, इतना साहित्य-सृजन, इतने व्यक्तियों का निर्माण वस्तुत: ये सब अद्भुत हैं। उन्हें हम क्रांति के साथ शांति के प्रवर्तक कह सकते हैं। उनकी जीवन-गाथा आश्चर्यों की वर्णमाला से आलोकित एक महालेख है। उसे पढ़कर मनुष्य एक उच्छ्वास, नई प्रेरणा, राष्ट्रीयता और नई प्रकाश-शक्ति का अनुभव करता है।

अन्तर्जगत् में महर्षि अरविन्द आत्मवान थे। आत्मा को समाहित कर वे आत्मवान् बने। जो आत्मवान् होता है, वही दूसरों का हृदय छू सकता है। उन्होंने जन-जन का मानस छुआ। प्रसन्न मन, सहज ऋजुता, सबके प्रति समभाव, आत्मीयता की तीव्र अनुभूति, राष्ट्रीयता एवं हिन्दुत्व का दर्शन, विशाल चिंतन, जातीय, प्रांतीय, साम्प्रदायिक और भाषाई विवादों से मुक्त- यह था उनका महान व्यक्तित्व, जो अदृश्य होकर भी समय-समय पर दृश्य बनता रहा। उन्होंने धर्म के शाश्वत सत्यों से युग को प्रभावित किया, इसलिए वे युगधर्म के व्याख्याता बन गए। उन्होंने नैतिक क्रांति एवं स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, इसलिए वे युगपुरुष और क्रांतिकारी कहलाए। वे संघर्षों की दीवारों को तोड़-तोड़ कर आगे बढ़े, इसलिए वे प्रगतिशील थे। सब वर्ग के लोगों ने उन्हें सुना, समझने का यत्न किया। वे सबके होकर ही सबके पास पहुंचे, इसलिए वे विशाल-दृष्टि थे।

देशभक्ति से प्रेरित महर्षि अरविन्द ने जानबूझ कर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र-सेवा करने की ठान ली। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे अत: उन्होंने इन्हें अपनी रियासत में शिक्षाशास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया। बडौदा में ये प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यतापूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान एवं देशभक्त बनाया। रियासत की सेना में क्रान्तिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया था। हजारों युवकों को उन्होंने क्रान्ति की दीक्षा दी थी। पुरुषार्थ की इतिहास परम्परा में इतने बड़े पुरुषार्थी पुरुष का उदाहरण कम ही है, जो अपनी सुख-सुविधाओं को गौण मानकर जन-कल्याण के लिए जीवन जीए। 5 दिसंबर, 1950 को इन्फ्रलुऐंजा महामारी के आक्रमण से महर्षि अरविन्द का देहावसान हो गया।

ब्रिक्स देशों ने कैसे उड़ा दिए अमेरिका के होश

अभिनय आकाश

किसी की जेब में किसी की तिजोरी में छोटे-बड़े बैंक में, बटुए से लेकर एटीएम तक में हर जगह मौजूद खास तरह के कागज से बने नोट हर दौर में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत रहा है। इसलिए तो दुनिया कहती भी है कि बाप बड़ा न भइया, सबसे बड़ा रुपैया। हर चीज से बढ़कर है ये, जिसके सिक्कों की खनक हो या करारे नोटों की खुश्बू हर कोई इसका दीवाना है। एक पुरानी लोकोक्ति है कि हाथी के पांव में सबका पाव होता है। जिसका अर्थ है बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार का ऐसा ही हाथी है। ब्रिक्स देश अब इस हाथी को चुनौती देने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ब्रिक्स देशों को धमकी दे दी।उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश की तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ झेलना पड़ेगा। यही नहीं यहां तक कह दिया कि फिस वे देश अमेरिकी बाजार तक पहुंचने का ख्वाब छोड़ दें। इस धमकी को गहराई से देखें तो समझ में आता है कि अमेरिका को अपने डॉलर का दबदबा घटता नजर आ रहा है। तभी तो ट्रंप ने ऐसी धमकी दी है। दुनियाभर में देशों के बदलते समीकरण भी अमेरिकी चिंता का एक बड़ा कारण है। ट्रम्प ने ये धमकी क्यों दी और डॉलर पर आंच आते ही अमेरिका इतना घबरा क्यों जाता है तमाम मुद्दों का आज एमआरआई स्कैन करते हैं।

ब्रिक्स 2009 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय ग्रुप है। इसके सदस्य देश है. ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2024 में इसका विस्तार हुआ और ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई भी इसमें शामिल हुए। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसका जाता उदाहरण भारत और चीन द्वारा रूस से तेल खरीदना है। इस सौदे के लिए डॉलर का उपयोग नहीं किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उसे लग रहा था कि बिना डॉलर रूस का तेल बिक नहीं पाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। भारत और चीन ने रूस से ताबड़तोड़ तेल खरीदा।

रूस और चीन ने अमेरिकी डॉलर का विकल्प लाने की कोशिश की है। ब्राजील ने भी एक साझा करंसी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। ब्रिक्स समिट से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस डॉलर को छोड़ना या उसे हराना नहीं चाहता है। उसे डॉलर के साथ काम करने से रोका जा रहा है। इसलिए डॉलर की जगह किसी दूसरे विकल्प को ढूढ़ना मजबूरी है। डॉलर की वैल्यू कम करने की ब्रिक्स देशों की इन्हीं कोशिशों से ट्रंप भड़के हुए हैं।

ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाते हुए एक्स पर लिखा कि हमें इन देशों से ये कमिटमेंट चाहिए कि वो न तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे। न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट बेचने को को गुडबॉय कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे किसी और मूर्ख को खोज सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा। जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए।

ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका से व्यापार करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करना जारी रखना होगा।

ट्रम्प की धमकी ऐसे समय में आई है जब रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप रूसी तेल को यूरोप से एशिया में पुनर्निर्देशित किया गया था। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी। बीआईएस त्रिवार्षिक सेंट्रल बैंक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, विदेशी मुद्रा बाजार का कारोबार (दैनिक औसत), दर्शाता है कि अमेरिकी डॉलर प्रमुख वाहन मुद्रा है, जो वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार का 88 प्रतिशत हिस्सा है। रुपये की हिस्सेदारी 1.6 फीसदी रही है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगर रुपये का कारोबार वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार में गैर-अमेरिकी, गैर-यूरो मुद्राओं की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत के बराबर हो जाता है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा माना जाएगा। ट्रंप को लगता है कि टूड मे डॉलर का कद घट रहा है और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन इस खतरे को अनदेखा कर रहे है।

ट्रंप की चेतावनी खासतौर पर रूस और चीन के लिए है। भारत ने स्पष्ट रूप से ब्रिक्स की साझा करंसी के विचार को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर में कहा था कि भारत अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल से बचना भारत की आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं है। जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी नीतियां अक्सर कुछ देशों के साथ व्यापार को जटिल बनाती हैं, और भारत कुछ अन्य देशों के विपरीत, डॉलर से दूर जाने का इरादा किए बिना समाधान की तलाश कर रहा है। हालाँकि, मंत्री ने कहा कि एक बहुध्रुवीय दुनिया अंतत: मुद्राओं और आर्थिक लेनदेन में परिलक्षित होगी। जयशंकर ने साफ कहा था कि मैं जो कहूंगा वह यह है कि हमारी स्वाभाविक चिंता है। हमारे पास अक्सर ऐसे व्यापार भागीदार होते हैं जिनके पास लेनदेन के लिए डॉलर की कमी होती है। इसलिए, हमें यह तय करना होगा कि क्या उनके साथ लेन-देन छोड़ देना चाहिए या वैकल्पिक समाधान ढूंढना चाहिए जो कारगर हों। डॉलर के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक शक्ति में असमानता को देखते हुए, स्थानीय मुद्रा पहल का समर्थन करते समय, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ढांचा चीन का असंगत रूप से पक्ष न ले।

विश्वयुद्ध के बाद से दुनियाभर में डॉलर का दबदबा है, क्योंकि इसे ही व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हर देश अपने रिजर्व में डॉलर को रखना चाहता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनियाभर के देश आपस में व्यापार करने के लिए अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए अमेरिका बैठे-बिठाए अरबों कमाता है। सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है। यानी भारत की इकोनॉमी से भी दोगुना ज्यादा। ट्रंप का बयान यह बयान ब्रिक्स देशों और अमेरिका के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। गौरतलब है कि चीन जैसे देश जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर रखते हैं, ताकि उन्हें सस्ता निर्यात करने का मौका मिले और साथ ही लार्ज ट्रेड सरप्लस का लाभ भी मिलेगा।

आज का इतिहास

1879 पहला स्वचालित फोन स्विचिंग प्रणाली तैयार की गयी।
1892 जॉन थॉम्पसन कनाडा के चौथे प्रधानमंत्री बने।
1893 एकाधिक मतदान न्यू साउथ वेल्स में समाप्त किया गया।
1893 टोरंटो में पहली इलेक्ट्रिक कार बनी जो एक बार चार्ज होने पर 15 मील चलती थी।
1916 ब्रिटिश प्रधान मंत्री एच. एच. अस्क्विथ ने महायुद्ध के संचालन में दृढ़ता की कमी के कारण इस्तीफा दे दिया।
1919 तुर्की के युद्ध मंत्रालय ने यूनानियों, अर्मेनियन और यहूदियों को सैन्य सेवा हटाया।
1926 फोरवेल के टेक्सास शहर में जॉर्ज हासेल ने अपनी पत्नी और आठ बच्चों की हत्या की।
1928 इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट क्रिकेट मैच 675 रनों से जीता।
1928 ब्रिसबेन में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 675 रनों से हराया था।
1932 सोवियत संघ ने सरकार के हाथों से खाद्य, कपड़े और अन्य आपूर्ति के वितरण को कारखानों में स्थानांतरित करने का फैसला किया। जनता को राशन कार्ड दिए जाने थे और यह माल खरीदने के लिए कारखानों तक था।
1933 संयुक्त राज्य अमेरिका में मादक पेय का निषेध उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका में ट्वेंटी-प्रथम संशोधन की पुष्टि की गई, अठारहवें संशोधन को निरस्त करते हुए।
1936 1936 का सोवियत संविधान, जिसे स्टालिन कॉन्स्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, को अपनाया गया।
1939 ब्राजील के पेड्रो II के अवशेष, जिन्हें एक गणतंत्र तख्तापलट कर बाहर निकाल दिया गया था, को फिर से दफनाने के बाद दफनाया गया था।
1945 पांच अमेरिकी नौसैनिक टीबीएफ एवेंजर टॉरपीडो बमवर्षकों का एक दल फ्लाइट 19 उस क्षेत्र में गायब हो गया जिसे अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है।
1950 चीनी सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र की वापसी के बाद अब उत्तर कोरियाई राजधानी प्योंगयांग पर हमला किया है।
1955 लंबी दूरी के टेलीफोन कॉल को घर घर की चीज बना देने वाली एसटीडी सेवा अस्तित्व में आई।
1956 गुलाब हेइलब्रॉन ब्रिटेन की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी।
1965 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में ग्लासनॉस्ट मीटिंग पहला प्रदर्शन बन गया और देश में नागरिक अधिकारों के आंदोलन की शुरुआत हुई।
1974 बर्मिंघम अमेरिकियों ने विश्व फुटबॉल लीग इतिहास में एकमात्र विश्व बाउल जीता।
1974 माल्टा गणराज्य घोषित हुआ।

'आप' यदि कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो सियासी तौर पर समाप्त हो जाएगी?

कमलेश पांडे

देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा होंगे और यहां पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एक बार फिर पूरे दम-खम से अकेले यह चुनाव लड़ेगी। जबकि वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की भागीदार पार्टी रही है। बताया जाता है कि हाइब्रीड पॉलिटिकल पार्टी आप को डर है कि यदि वह कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो सियासी तौर पर समाप्त हो जाएगी! पंजाब और दिल्ली की राजनीतिक परिस्थिति भी इसी बात की चुगली करती है।

कहना न होगा कि छोटा हिंदुस्तान समझा जाने वाला दिल्ली प्रदेश का विधानसभा चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए काफी अहमियत रखता है। यहां पर पहले कांग्रेस और उसके बाद भाजपा का शासन रहा है। बाद में भी इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सत्ता की अदला-बदली हुई। लेकिन दिल्ली की स्थानीय पार्टी के तौर पर आप के राजनैतिक अभ्युदय ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के समक्ष एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ा कर दी, जो अब तलक जारी है। समझा जाता है कि कभी केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के जबड़े से 2013 में उसकी सूबाई सत्ता छीनना और फिर केंद्र में सत्तारूढ़ हुई भाजपा के कसते सियासी शिकंजे के बावजूद 2015 और 2020 में भी यहां की सत्ता को बचाए रखना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता है, जिसके लिए उन्हें नाकोचने चबाने पड़े। इसके ही खातिर उन्हें तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा, जहां से फिलवक्त बेल पर वह बाहर हैं। दरअसल, हाइब्रीड पॉलिटिकल पार्टी आप एक अलबेली राजनीतिक पार्टी है, जो कई मामलों में भाजपा और कांग्रेस से अलग है तथा क्षेत्रीय दलों से काफी आगे है। कांग्रेस एवं उसकी विरोधी रही जनता पार्टी व जनता दल और भाजपा के अलावा आप एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो एक के बाद दूसरे राज्य में अपने बलबूते सरकार बनाने में सफल हुई और सफलता पूर्वक उसका संचालन कर रही है। युवा पेशेवरों की यह पार्टी तमाम विवादास्पद मुद्दों में निष्पक्ष अंदाज रखती आई है। हालांकि, केंद्रीय सत्ता तक पहुंचना अभी भी उसके लिए नई दिल्ली दूर है जैसा प्रतीत होता है।

हालांकि इंडिया गठबंधन की शोहबत और भाजपा के धूर विरोध में आप को भी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति अपनानी पड़ी है। आरक्षण सम्बन्धी दुविधाजनक स्टैंड लेना पड़ा। भ्रष्टाचार के अंध कुएं में गोते लगाने पड़े हैं। शानोशौकत के वास्ते शीश महल (मुख्यमंत्री का आवास) तक बनवाने पड़े। वहीं, जनता को रिश्वत स्वरूप मुफ्त बिजली-पानी देने की उसकी शुरुआत और शिक्षा-स्वास्थ्य सम्बन्धी जनसुविधा आज सभी पार्टियों के एजेंडे में शामिल हो चुका है। इसे भारतीय राजनीति में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जिसकी शुरुआत आप ने की है। कांग्रेस/भाजपा आदि तो इस मामले में अब आप से भी दो कदम आगे बढ़ चुके हैं। देखा जाए तो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं जिसमें अपनी भरोसेमंद सहयोगी मंत्री रहीं आतिशी मर्लेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जाना भी शामिल है।

वहीं, हाल ही में उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। शायद यह हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप के प्रति कांग्रेस की ओर से दिखाई गई राजनीतिक बेरुखी का असर और प्रतिक्रिया स्वरूप करारा जवाब है, क्योंकि तब भी कांग्रेस-आप का गठबंधन टूट गया था। फ़लसफ़ा यह निकला कि कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में आ नहीं पाई और वहां पर अपने बलबूते चुनाव लड़ी आप का खाता तक नहीं खुला, जबकि यह आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का गृह प्रदेश भी है। हालांकि यह बात सभी जानते हैं कि गठबंधन में रहते हुए भी आप ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस से अपने वर्चस्व वाले एक प्रान्त दिल्ली में गठबंधन तो दूसरे प्रान्त पंजाब में दोस्ताना संघर्ष किया। इस दौरान आप पार्टी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से मात्र 3 सीटें ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं। यही बात आप को अखड़ गई।

वहीं, दिल्ली में भी उसने लोकसभा की 7 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस को दी थी, लेकिन दोनों पार्टियां यहां जीरो पर आउट हो गईं। क्योंकि यहां भी सियासी तालमेल नदारत दिखा था। परिणाम यह हुआ कि सातों लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत गई, जो पहले भी सभी सीटों पर काबिज थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी कांग्रेस? क्योंकि जहां जहां भी त्रिकोणीय मुकाबले की नौबत आती है तो अक्सर सत्ता पक्ष फायदे में रहता है। आप के लिए यह स्थिति यहां भी फायदेमंद हो सकती है। चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की लगभग सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। जिससे यह तय हो चुका है कि दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी। ऐसे में आप से यादा कांग्रेस का चुनावी सफर मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं, गठबंधन में फूट की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जैसे ही दिल्ली विधान सभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दो अहम दलों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से साफ संकेत मिला कि इस बार दोनों पार्टियां चुनावी रण में एक-दूसरे के सामने खड़ी होंगी। तो सबसे यादा चर्चा कांग्रेस को लेकर चलने लगी। क्योंकि जो कांग्रेस कुछ वक्त पहले तक अरविंद केजरीवाल के खातिर बीजेपी से लड़ रही थी। अब वहीं कांग्रेस आखिर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलेगी, यक्ष प्रश्न है?

हालांकि मौजूदा सियासत में विचारों का उलट फेर एक आम सी बात हो गई हैं। चूंकि दिल्ली की जनता सूझबूझ वाली है। ऐसे में कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की स्थिति में नहीं है। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस और आप के बीच रिश्ते स्वार्थ वाले रहे हैं। मसलन, जिस आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया था, वही आम आदमी पार्टी जब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अलबत्ता, कांग्रेस ने भी अपने सियासी फायदे को देखकर आप से हाथ मिलाने में ही समझदारी समझी, क्योंकि बीजेपी से अकेले टकराना, दोनों पार्टियों के बस से बाहर था। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को इससे आप से यादा फायदा मिला। खासकर पंजाब में वह आप से दुगुनी से अधिक लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। जबकि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता इस सांठगांठ को अछे समझ गई। इसलिए लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी के गठबंधन को नकार दिया।

जिस तरह से आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना से बीते रविवार को इनकार किया, उससे इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि, दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि आप और कांग्रेस 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा हैं। दोनों दलों ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर गठबंधन को जीत नहीं मिली थी और सभी 7 सीट बीजेपी ने जीती थीं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा

की 70 सीटों के लिए 2025 में चुनाव होंगे। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थीं। वहीं बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। इस बार भी कांग्रेस की दिल्ली में मजबूत स्थिति नहीं है। ऐसे कांग्रेस मुकाबले में दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। याद दिला दें कि कांग्रेस ने 2008 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी। 2008 में कांग्रेस को 40.31 फीसदी वोट मिले थे।

हालांकि, साल 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। वर्ष 2008 में जहां पार्टी का वोट प्रतिशत 40 फीसदी था, वो वर्ष 2013 में घटकर 25 प्रतिशत पर आ गया था। वहीं, साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, जब उसे 10 फीसदी से भी कम वोट मिले और उसे एक भी सीट नहीं मिली। कहने का तातपर्य यह कि सिर्फ 7 सालों में ही कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40 से घटकर 9.7 फीसदी पर आ गया। उसके बाद वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव भी उसके लिए बुरा साबित हुआ। तब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2015 से भी कम हो गया है। इस बार कांग्रेस को 4.26 प्रतिशत वोट मिले थे। ये पिछले 12 सालों में पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। बावजूद इसके, कांग्रेस की ओर से भी पहले ही संकेत दिया चुका है कि वह दिल्ली विस चुनाव के रण में अकेले ही उतरने वाली हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने पिछले कुछ दिनों से आप और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी है। हाल ही में एक साक्षात्कार में स्व. शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। इससे साफ संकेत है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के मूड में है। वहीं कांग्रेस के कई स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस बात को लेकर भी कांग्रेस का टेंशन और गुस्सा दोनों बढ़ा हुआ है।

ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की जनता को अपना एजेंडा समझाने में होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के बचाव में बयान दे रहे थे। वही नेता अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। लिहाजा, दिल्ली की जनता भी कांग्रेस के रवैये को देखकर कन्फ्यूजन में है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर भी कांग्रेस पहले चुप थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस, आप को इस घोटाले से घेर रही है। इसलिए दिल्ली में कांग्रेस का किरदार फिलहाल जनता की समझ से बाहर लग रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी और आप के सामने कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं, केजरीवाल के बयानों से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चर्चा चली थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। वहीं दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन को लोकसभा चुनाव में सात में से एक भी सीट नहीं मिली थी। पंजाब में दोनों दल एक-दूसरे के ख़िलाफ़ चुनावी मैदान में उतरे। दोनों दलों के बीच ये उतार-चढ़ाव वाली दोस्ती आप के बनने के बाद से ही चल रही है। यहां पर एक बात याद दिलाना जरूरी समझता हूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप को 1.79 फ़ीसदी वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को 39.94 प्रतिशत तो कांग्रेस के खाते में 39.09 प्रतिशत मतदान गया। वहां बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर सरकार बना ली। वहीं कांग्रेस को 37 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। जबकि आप का खाता भी नहीं खुला। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच के वोट में अंतर सिर्फ 0.85 का था।

लिहाजा साफ है कि आप और कांग्रेस साथ आते तो शायद बीजेपी को हरियाणा में फायदा नहीं होता। कुछ ऐसा ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है, बशर्ते कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाये। हालांकि, दिल्ली में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि, यहां आप और कांग्रेस दोनों का मतदाता बेस एक ही है। इसलिए दोनों चाहते हैं कि हम बढ़े तो हम बढ़ें और इस कारण से समझौता नहीं हो पाता। हालांकि, उन्हें इस बात का रास्ता तलाशना चाहिए कि तमाम विरोधाभाषों के बीच आपस में कैसे सहयोग करे, ताकि भाजपा को यहां फायदा नहीं मिले? लेकिन दिल्ली में दिक्कत यह है कि यहां पर यदि कहीं आप बढ़ेगी तो कांग्रेस के क्षेत्र में बढ़ेगी और कहीं कांग्रेस बढ़ेगी तो आप का बढ़ना रुक जाएगा। इस कारण दोनों का समझौता दिल्ली में नहीं हो पाता।

यह ठीक है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन राजनीतिक मजबूती से होते हैं, पर कांग्रेस दिल्ली में इस समय काफी कमजोर है। बावजूद वह अपने प्रभाव वाले रायों में सहयोगियों को तवजो नहीं देती है। इसलिए सहयोगी भी अब अपने प्रभाव वाले राय में उसे तवजो नहीं दे रहे हैं। उत्तरप्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव में जो कांग्रेस विरोधी शुरुआत की, उससे दिल्ली के आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी प्रभावित हैं। बताया जाता है कि अब अरविंद केजरीवाल भी यूपी उपचुनाव की तरह ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में जोखिम लेने को तैयार हैं, क्योंकि अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से यह जाहिर हो गया है कि कांग्रेस अपने बूते पर बीजेपी से टक्कर लेने में सक्षम नहीं है और वह अपने सहयोगियों को भी जितवाने में सक्षम नहीं है। यूपी उपचुनाव का ताजा परिणाम भी सबके सामने है, जहां बीजेपी के मुकाबले सपा टिक नहीं सकी। इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एकला चलो का राग अलाप रहे हैं।

अलबत्ता, अरविंद केजरीवाल के बयान से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर एक और बड़ा प्रश्न चिह्न लग गया है! बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में चाहते थे कि इंडिया का घटक दल होने के नाते कांग्रेस उनको कुछ सीटें दे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जीत के उत्साह में केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया। इसलिए अब केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस को दिल्ली में पांच से दस सीटें भी दें। वहीं, कांग्रेस के साथ दुविधा ये है कि वह अपने बूते दिल्ली में शून्य है। तीसरी बार ऐसा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुले। उल्लेखनीय है कि 2015 और 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसके वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट आती गई। राजनीतिक मामलों के जानकार भी बताते हैं कि आप का उदय तो कांग्रेस के ख़िलाफ़ हुआ। दिल्ली के बाद पंजाब में भी उसने कांग्रेस से ही सत्ता झटकी। हां, एमसीडी चुनाव में आप पहली बार बीजेपी को सीधे गचा देने में सफल रही। पंजाब में आप और कांग्रेस एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ही लड़े। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं था। आप का जो भी विकास हुआ वो तो कांग्रेस के विरोध के रूप में ही हुआ। क्योंकि आप के जन्म के समय तो कांग्रेस ही केंद्रीय और दिल्ली दोनों की सत्ता में काबिज थी। तब आरएसएस का उसे गुप्त सहयोग हासिल था।

बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहीं और एक सफल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के रूप में चर्चित नेत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस भी 2013 के विधानसभा चुनाव में नवगठित पार्टी आप से हार गई। क्योंकि तब आप के खाते में बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के भी वोट गए। हालांकि, बीजेपी के दिल्ली में 30 फीसदी से अधिक वोटर बने हुए हैं, जिससे यहां की सत्ता में उसकी वापसी की संभावना जिंदा है, जबकि कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। आंकड़े गवाह हैं कि वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को 70 सीटों में से 28 सीटों के साथ 29 फ़ीसदी से अधिक वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को 31 सीटें मिली थी और उसका वोट 30 प्रतिशत के आसपास बना रहा। तब, कांग्रेस को 10 सीटें और 24 फ़ीसदी से अधिक वोट मिले थे। हालांकि, इस चुनाव में बीजेपी 31 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा आप का साथ दिए जाने से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि, दोनों का साथ 50 दिन भी नहीं चल पाया था। वहीं, वर्ष 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ने 67 सीटें जीती, जबकि बीजेपी महज 3 सीट पर ही सिमट गई। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10 फीसदी के करीब रहा, लेकिन सीट एक भी नहीं। वहीं, बीजेपी का वोट प्रतिशत इस चुनाव में भी 30 फ़ीसदी से अधिक बना रहा।

वहीं, वर्ष 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को 62 सीटें 53 प्रतिशत से यादा वोट के साथ मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 35 फीसदी से अधिक मत मिले, लेकिन इसमें कांग्रेस मात्र पांच प्रतिशत के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। अब ये तो दिल्ली में अगले साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि किसे कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस के लिए राह काफी मुश्किल होने वाली है। कहा भी जाता है कि अपने फायदे के लिए राजनेतागण कुछ भी कर सकते हैं। कौन सहयोगी कब प्रतिद्वंदी बन जाए और कौन प्रतिद्वंदी कब सहयोगी बन जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। हालांकि जनता को इसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ता है। सवाल यह भी उठा कि आप और कांग्रेस की दोस्ती बनती और टूटती क्यों रहती है? क्या सिर्फ इसलिए कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर था कि साल 2023 में आप ने उस कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी, जिसके ख़िलाफ़ वो प्रचार करके चुनावी मैदान में उतरी थी। इसके बाद से आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता और टूटता रहता है। ऐसे में सवाल ये है कि आख़िर बीजेपी के ख़िलाफ़ बने गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और आप एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे? क्या यह महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के बाद कांग्रेस की सिमटती सियासी हैसियत का साइड इफेक्ट्स है, जिसका दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच के आपसी रिश्तों पर असर हुआ है? या फिर हाइब्रीड पॉलिटिकल पार्टी आप समय रहते ही यह बात समझ चुकी है कि यदि वह कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो सियासी तौर पर समाप्त हो जाएगी, आज नहीं तो निश्चय कल!

मोहन भागवत की सलाह पर स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत

कृष्णमोहन झा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान अक्सर देश में एक नई बहस को जन्म देते हैं लेकिन कई बार यह भी देखने में आता है कि वे जब व्यापक राष्ट्रीय हित से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय व्यक्त करते है तब उस पर सार्थक विमर्श का हिस्सा बनने के बजाय संघ के प्रति पूर्वाग्रही वर्ग उसे एकदम खारिज करने की कोशिशों में जुट जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला एक लंबे अरसे से चला आ रहा है लेकिन हर बार संघ प्रमुख की महत्वपूर्ण राय पर सार्थक बहस के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ प्रमुख की राय की न तो अनदेखी की जानी चाहिए,न ही उस पर पूर्वाग्रही दृष्टि कोण अपनाया जाना चाहिए।

ताज़ा मामला संघ प्रमुख के द्वारा दिए गए उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने देश की प्रजनन दर में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए हर दम्पत्ति को तीन बच्चों को जन्म देने की सलाह दी है । संघ प्रमुख के इस बयान पर भी टीका टिप्पणी का सिलसिला प्रारंभ हो गया है परन्तु चिंताजनक रूप से गिरती हुई प्रजनन दर और उसके प्रभावों पर विचार करें तो संघ प्रमुख की राय की सार्थकता पर सवाल उठना मुश्किल प्रतीत होता है। गौरतलब है कि अतीत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इसी तरह की राय व्यक्त कर चुके हैं। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश सरकार टू चाइल्ड पालिसी भी वापस ले ली थी जिसके तहत दो से अधिक संतानों के माता-पिता पिता को स्थानीय चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2005 में तत्कालीन सरसंघचालक सुदर्शन जी ने भी कहा था कि दो या एक बच्चे के नियम में नहीं फंसना चाहिए । उनके कथन का आशय था कि हर दम्पत्ति को कम से कम तीन बच्चों को जन्म देना चाहिए।

मोहन भागवत गत दिनों नागपुर में आयोजित कुठाले कुल सम्मेलन को संबोधित करते हुए जब यह कह रहे थे कि देश में हर दम्पत्ति को तीन बच्चों को जन्म देना चाहिए तब वे भली भांति यह भी जानते थे कि उनकी इस सलाह की टीका टिप्पणी अवश्य होगी इसलिए उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इस सलाह का आधार क्या है। भागवत ने कहा कि जब किसी समाज की जनसंख्या दर 2.1 से नीचे चली जाती है तब वह

समाज नष्ट हो जाता है । जनसंख्या दर नीचे चली जाने से , कोई संकट न होने के बावजूद वह समाज नष्ट हो जाता है। बहुत से समाज और भाषाएं इसीलिए विलुप्त हो गए। इसलिए जनसंख्या दर को 2.1 बनाए रखने के लिए तीन बच्चे पैदा करना चाहिए।

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि 1998 या 2002में हमारे देश की जो जनसंख्या नीति तय की गई थी उसमें यह कहा गया था कि जनसंख्या दर 2.1 से कम नहीं होना चाहिए इस दर में को बनाए रखने के लिए हर दम्पत्ति के दो से अधिक बच्चे होने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोहन भागवत की इस सलाह पर राजनीति भी गर्मा गई है । कुछ राजनीतिक दल इसके विरोध में मुखर हो उठे हैं तो कुछ दलों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करना ही उचित समझा है। दरअसल देश की जनसंख्या दर में गिरावट पर मोहन भागवत की चिंता को एकदम खारिज करने से पहले यह सोचने की भी आवश्यकता है कि जनसंख्या दर में गिरावट के और क्या परिणाम हो सकते हैं। जनसंख्या दर में गिरावट के इस परिणाम के बारे में तो मोहन भागवत ने सचेत कर ही दिया है कि जिस समाज में जनसंख्या दर 2.1 से नीचे चली जाती है वह समाज विलुप्त हो जाता है। अगर चीन जर्मनी और जापान जैसे देशों के उदाहरण से समझें तो ज्ञात होगा कि वहां जनसंख्या दर घटने से वर्किंग पापुलेशन तेजी से घट रही है और बुजुर्गो की आबादी बढ़ रही है।इसी कारण चीन और सिंगापुर जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। अब जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है तब हमें भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक से अधिक युवा आबादी की जरूरत होगी। किसी भी देश की प्रगति में युवा शक्ति का महत्व पूर्ण योगदान होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह में भी यही संदेश छुपा हुआ है इसलिए उनकी सलाह पर अनावश्यक टीका टिप्पणी के बजाय उस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए।

दिल्ली सल्तनत पर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई?

डॉ. रमेश ठाकुर

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमर्रा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रूक गए।

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड़ में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया।

दिल्ली पहुंचने के लिए गौतमबुद्ध नगर से करीब 50,000 से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए, फिर उन्होंने दिल्ली कूच का प्लान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में

दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस समय एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती है। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामझाम लेकर पहुंच हैं। राशन, टैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि है उनके पास।

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगो को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्हें ज़मीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगे भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंड़ियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। ये मांगे ऐसी जिसे शायद ही सरकारें मांगे।

प्रतीत ऐसा होता है कि ये किसान मूवमेंट भी बडा रूप ले सकता है। अभी तक गनीमत ये समझी जाए, इस मोर्चे में सिर्फ दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि बाहर से करीब सौ से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई जल्द विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदने में देर नहीं करेंगे। हांलाकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफ़िक पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी की गई जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस-वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई, क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग अनचाई परेशानी से जूझते दिखाई पड़े, स्कूली बच्चों भी जाम में फंसे रहे, एमबूलेंस भी नहीं निकल पाईं। नौकरीपेशा समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा।

किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे की उनको किसी आंतकवादी को रोकना या पकड़ना हो? किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवज़ा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं इसमें बुरा क्या है? वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती तो है नहीं? फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला किया। बोले, किसानों पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं प्रधानमंत्री। उनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें आने देना चाहिए, उनपर वाटर कैनन का प्रयोग करना गलत है। दरअसल, ऐसे मौकों पर विपक्ष का बिना सोचे समझे कूद पड़ना, 'आग में घी डालने' का काम कर जाता है। जबकि, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर विकल्प और समाधान की ओर ध्यानाकर्षण करवाना चाहिए। ताकि सरकार आंदोलनकारियों से बात करने पर विवश हो? पर, दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं पाता और न ही विपक्ष ऐसा प्रयास करता है।

हमारा आधार गांव है। गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज शहरों की चकाचौंध करने वाली तरक्की गांवों के बदौलत ही है। यह विलेज इकोनॉमी ही है जो देश की तरक्की का ताकतवर इंजन बन रही है। तरक्की का यह सिलसिला आगे भी तेजी से चलता रहे, इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत अव्वल रहना जरूरी है। इस बात को सरकार अच्छी तरह समझ रही है।

ग्राम रोजगार

ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि एक पूरा गणतंत्र हो, जो अपनी सबसे जरूरी आवश्यकताओं के लिए भी अपने पडोसियों पर निर्भर न हो। सालों पहले महात्मा गांधी के दिए ये विचार आज के संदर्भ में भी सटीक हैं। ऐसा हो भी क्यों न, भारत जैसे देश में जहां 60 फीसदी से ज्यादा लोग कृषि से जुडे हों, कुल जीडीपी में जिसकी हिस्सेदारी 18 फीसदी के आस पास हो, तो उसकी खुशहाली बगैर गांवों की खुशहाली के कैसे मुमकिन है? अमूमन कहा भी जाता हैं कि किसी भवन की मजबूती उसके आक र्षक शिखरों से नहीं, बल्कि उसके आधार से तय होती है। हमारा आधार गांव है। गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज शहरों की चकाचौंध करने वाली तरक्की गांवों के बदौलत ही है। यह विलेज इकोनॉमी ही है जो देश की तरक्की का ताकतवर इंजन बन रही है। तरक्की का यह सिलसिला आगे भी तेजी से चलता रहे, इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत अव्वल रहना जरूरी है। इस बात को सरकार अच्छी तरह समझ रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षो में सरकारी योजनाएं गांवों की तरफ उन्मुख हुई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, रुरल हाउसिंग स्कीम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनाएं खास हैं। सरकार ही नहीं निजी क्षेत्र भी अपनी नई योजनाएं गांव को फोकस करके निकाल रही है और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है।

दरअसल पिछले दो दशकों से देश में औद्योगिकीकरण का पहिया तेजी से घूमा है। इस दौरान देश में बाजारवादी संस्कृति बढी है, नए अवसर भी पैदा हुए हैं, तो लोगों के पास धन की आमद में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इन सबका सीधा असर हमारे जीवन की गुणवत्ता पर पडा है। पर ज्यादा फायदे में शहर ही रहे। जो इस दौरान तेजी से विकास के एपीसेंटर्स व पूंजीगत गतिविधियों के हार्टलैंड बने। विकास की यह रफ्तार गावों से लोगों के शहरों की ओर पलायन का कारण भी बनी। जहां बेहतर जीवन की तलाश में हर रोज लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले सालों में देश में काफी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे। इसलिए यह आज की जरूरत है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस दबाव पर काबू पाया जाए, लोगों को उनके स्थान पर ही रोजगार व बाकी सहूलियतें मुहैया कराई जाएं। इन्हीं सब चीजों के कारण आज ग्राम आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण मसला बन चुका है। इसके अंर्तगत, आने वाले सालों में गांवों ही में रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, संचार, शिक्षा के इतने अवसर पैदा किए जाएंगे कि शहर पलायन ग्रामीणों की मजबूरी नहीं बनेगी। देश के गांवों का वृहत विकास तभी संभव है, जब अधिक से अधिक प्रोफेशनल्स को वहां रोजगार के मौके मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए सरकारी और निजी क्षेत्रों के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित काफी कोर्स विभिन्न संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं और ट्रेंड प्रोफेशनल्स गांव में रहकर ही कॅरियर की ऊंची उडान भर रहे हैं और साथ ही सामाजिक दायित्व का निवर्हन करके आत्मसंतोष भी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी गांव में रहकर देश के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं, तो आपके पास अवसरों का पिटारा है।

कोर्स व योग्यता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतगर्त कृषि से लेकर, पशुपालन, कपास, रेशम निर्माण के साथ स्वरोजगार के कई दूसरे साधन को प्रमुखता दी जाती है। देश के अलग अलग संस्थान इन क्षेत्रों में कोर्स ऑफर करते हैं, जिनमें दाखिले की न्यूनतम योग्यता 12वी उत्तीर्ण माना जाता है तो वहीं कई संस्थानो में 10 वीं के बाद से डिप्लोमा कोर्स का भी प्रावधान है। कहने का आशय यह है कि इसमें मैनेजमेंट कोर्स से लेकर स्त्रोजगार से संबंधित कई तरह के कोर्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप गांव में रहकर कर सकते हैं।

राहें और भी

एग्रो इकोनॉमी आज रोजगार की राह में बेहतरीन अवसरों का सृजन कर रही है, जिसमें कुटीर से लेकर मझोले, बडे उद्योग तक अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं। जहां कुटीर उद्योग में नाम मात्र की पूंजी व मानव शक्ति की दरकार होती हैं, तो वहीं कई उद्योग ऐसे भी हैं, जहां आप कुछ निवेश के जरिए खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उद्योग अपनी बडी भूमिका तलाश चुके हैं। महिलाओं के लिए भी यहां अच्छे अवसर हैं। सहकारी उद्यम, स्वयं सहायता समूह,सस्ते ऋण, तकनीकी सहायता जैसे प्रयास इस क्षेत्र की संकरी पगडंडियों को कामयाबी के राजपथ में बदल रहे हैं। स्थानीय या ग्राम स्तर पर मसाला, कपास छंटाई, फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, रुई, आयल, जूट, गन्ना, राइस मिल्स आदि विलेज इकनॉमी से सीधा संबध रखते हैं।

फ्यूचर प्रॉसपेक्ट

इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री का तेजी से प्रवेश हो रहा है। एसोचैम के एक अध्ययन के मुताबिक, आज रूरल रिटेल मार्केट का आक ार 113 बिलियन डॉलर का हो चुका है जो देश के कुल रिटेल मार्केट का 40 प्रतिशत है। इस बडे मार्केट के अपार फायदों को पाने के लिए देश के बडे बडे कॉरपोरेट ग्रुप्स गांवों का रुख कर रहे हैं। केवल यही नहीं 425 बिलियन डॉलर का रूरल कंज्यूमर मार्केट भी आज मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसके साथ रूरल सर्विसेज इंडस्ट्री व 44 फीसदी वार्षिक की दर से बढती रूरल हेल्थ केयर इंडस्ट्री गांवों में बेशुमार अवसर पैदा कर रही है। देखा जा रहा हैकि ग्रामीण मार्केट को कब्जे में लेने के लिए कंपनियों में एक होड सी मची है, जो ग्राम व ग्रामीण युवाओं दोनो को फायदा पहुंचा रही हैं। देश में एग्रो इकनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने छोटे बडे स्तर पर कई संस्थानों की स्थापना की है। जिसमें देश के मैनेजमेंट संस्थानों के अलावा कृषि विश्वविद्यालय हैं।

रूरल में मैनेजमेंट

देश की इकोनॉमी में गांवों का योगदान कोई रहस्य नहीं रह गया है। खुाद भारत जैसे देश में जहां बहुसंख्य आबादी गांवों मे रहती हो, रूरल मैनेजमेट की अवधारणा और पुख्ता हो जाती है। दरअसल प्रोफशनल रूरल मैनेजर्स का काम ग्रामीणों की विकास परक गतिविधियों में सहयोग व सलाह देना होता है। इन सलाहों में फसल उत्पादन, फसलों के व्यवसायिक प्रबंधन, जल संचयन, टीकाकरण, मृदा सुधार, उद्यमशीलता जैसी चीजें होती हैं। विकास के चक्के को तेज करने के लिए रूरल मैनेजर्स की भूमिका अहम मानी जा रही है। एक ओर जहां ज्यादातर प्रबंधन कॉलेज रूरल मैनेजमेंट को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, बैंककर्मी, एनजीओ भी तेजी से रूरल मैनेजमेंट के गुर सीख रहे हैं।

रूरल कंज्यूमर मार्केट

आज रूरल कंज्यूमर मार्केट देश के सबसे तेजी से बढते सेक्टर्स में एक है। इसकी ग्रोथ रेट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता हे कि 2004-05 की तुलना में आज इस क्षेत्र का विस्तार दोगुना हो चुका है। देश में रूरल कंज्यूमर मार्केट का कुल बाजार 425 बिलियन डॉलर के आंकडे को छू रहा है। इसका यह विस्तार इन दिनों ग्रामीण युवाओं के सपनों को भी विस्तार दे रहा है।अपने नेटवर्क के प्रसार में आज कंपनियां बडी संख्या में योग्य ग्रामीण को नियुक्तियां दे रही हैं।

हार्टीकल्चर है हॉट

बागवानी का क्षेत्र वैसे तो कृषि से जुडा हुआ है, लेकिन आज बागवानी उत्पादों की बढी मांग के बीच यह क्षेत्र एक पृथक व्यवसायिक सेक्टर के तौर पर उभरा है। बागबानी के अंर्तगत सभी प्रकार के फलों, सब्जियों का उत्पादन, कीटों की रोकथाम, उत्पादन बढोत्तरी जैसी चीजें आती हैं। इस क्षेत्र के मौजूदा ढांचे में जॉब्स की कोई कमी नही है। इस क्षेत्र में आप बतौर विशेषज्ञ, सुपरवाइजर, हार्टीकल्चर स्पेशलिस्ट, फ्रूट वेजीटेबल इंस्पेक्टर काम कर सकते हैं।

■ दीपिका देव

बीएसएफ भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ महत्वपूर्ण संशोधन

सीमा सुरक्षा बल ने बीते 20 नवंबर 2024 को एक शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके माध्यम से बीएसएफ के सिलेक्शन प्रोसेस में महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की गई है। बता दें कि यह बदलाव कई पदों को प्रभावित करते हैं। जिसमें एसएमटी वर्कशॉप, पशु चिकित्सा स्टाफ, इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन), पैरामेडिकल स्टाफ, एयर विंग, वाटर विंग और इंजीनियरिंग सेटअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप बी और सी के पद शामिल हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाले बदलावों और भर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं।

जानिए क्या बदलाव हुआ

बता दें कि अब सीमा सुरक्षा बल तीं प्रक्रिया कई चरणों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित करवाई जाएगी। जिसमें पहले चरण में शारीरिक मानक परीक्षण यानी की क्स्ज्ञ और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल है।

ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक पीएसटी में उम्मीदवारों की ऊंचाई, छाती और वजन का आकलन होगा। वहीं क्स्ज्ञ और क्श्वज्ञ पास करने वाले अभ्यर्थी एग्जाम में बैठ सकेंगे। इस परीक्षा में उम्मीदवार के ज्ञान और योग्यता का आकलन किया जाएगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के आखिरी चरण में अभ्यर्थियों का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से पास होना होगा।

भर्तियां

- बीएसएफ इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन) भर्ती 2024
- बीएसएफ पशु चिकित्सा स्टाफ भर्ती 2024
- बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप भर्ती 2024
- बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2024
- बीएसएफ एयर विंग भर्ती 2024
- बीएसएफ वाटर विंग भर्ती 2024 (ग्रुप ए, बी, सी पद)
- बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप भर्ती 2024 (ग्रुप ए, बी, सी पद

अंतिम चरण

डॉक्यूमेंटेशन- लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करानी होगी।

ट्रेड टेस्ट- ट्रेड आधारित पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने व्यवहारिक कौशल का आकलन करने के लिए ट्रेड टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

मेडिकल टेस्ट-इन चरणों के बाद उम्मीदवार को संबंधित पदों के लिए जरूरी स्वास्थ्य मानकों के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

हरियाणा सरकार की स्कीम आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाएंगे फ्री में पासपोर्ट

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी के आईटीआई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हरियाणा सरकार मुफ्त में पासपोर्ट बनाकर देगी। इस सरकारी स्कीम का फायदा केवल हरियाणा के आईटीआई स्टूडेंट्स को मिलेगी। इसके लिए छात्रों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। छात्रों के पास हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होना चाहिए। इतना ही नहीं, जिन स्टूडेंट्स के कोर्स के दौरान उपस्थिति कम से कम 80 फीसदी रही हो। आपको बता दें कि, आईटीआई कोर्स की अंतिम परीक्षा में बैठने के लिए संस्थान द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जाएगा। इसे छात्रों को पासपोर्ट एप्लिकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना जरुरी है। ये पासपोर्ट स्टूडेंट्स के संबंधित आईटीआई संस्थान द्वारा ही फ्री में बनवाए जाएंगे। फ्री पासपोर्ट स्कीम का मकसद टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने देश के साथ ही विदेशों में भी नौकरी के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। गुड़गांव सेक्टर- 14 स्थित गर्ल्स आईटीआई के प्रिंसिपल जेपी यादव ने बताया कि आईटीआई में कोर्स पूरा करने के बाद कोई छात्र विदेश जाना चाहता है, तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इसलिए यह सुविधा छात्रों को दी जा रही है।

रुतबेदार विकल्प है वकालत

आजकल आए दिन नई-नई मल्टी नेशनल कंपनियाँ स्थापित हो रही हैं। ऐसी जगहों पर वकीलों की आवश्यकता होती है और जितनी बड़ी कंपनी, आमदनी और रुतबा भी उतना ही बड़ा। आज जब हम ऐसी नौकरी बात करते हैं जिसमें मन मुताबिक काम करने की पूरी आजादी हो और उस नौकरी का एक रुतबा भी हो तो ऐसे में वकालत एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

साथ पढ़ना, लिखना और बोलना पसंद है।

आपको घंटों तक काम करना पड़ सकता है और कानूनी दांव पेचों पर सिर खपाना पड़ सकता है। परंतु इस काम के लिए आपको काफी सावधानी बरतनी होती है। आजकल आए दिन नई-नई मल्टी नेशनल कंपनियां स्थापित हो रही हैं। ऐसी जगहों पर वकीलों की आवश्यकता होती है और जितनी बड़ी कंपनी, आमदनी और रुतबा भी उतना ही बड़ा। भारत में लीगल शिक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होती है।

एलएलबी का अर्थ अपराध से जुड़े मामलों का वकील बनना नहीं है। इस कोर्स के बाद आप बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इनवायरनमेंटल लॉ, पेटेंट लॉ, टैक्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, रियल एस्टेट लॉ, लेबर लॉ, साइबर लॉ आदि में भी मजबूत स्थिति बना सकते हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिति

2007-08 के आँकडों के मुताबिक लॉ स्कूलों से जो ग्रेजुएट हुए लोगों को विभिन्न संस्थाओं में 30 हजार से 1 लाख रुपए प्रति माह तक की आय पर नियुक्त किया गया। इस वर्ष के आँकड़े और अधिक बेहतर स्थिति दर्शाते हैं। एक फ्रैशर भी अपने आत्मविश्वास के बल पर ये डिग्री हासिल करके अच्छा वेतन पा सकता है।

इंडिया एक कॉमन लॉ देश है जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ की कानून प्रणाली कई अन्य देशों की प्रणाली से मेल खाती है। जिस वजह से भारत में लॉ की डिग्री प्राप्त कर आप विदेश में भी अच्छी नौकरी पा सकते हैं, सिंगापुर, मलेशिया जैसे स्थानों पर भारतीय वकीलों की मांग लगातार बढ़ रही है।

बस कानूनी दाँव-पेच में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। अगर आपको कानून की धाराएँ मुँह जुबानी याद हो जाएँ और तार्किक शक्ति में इजाफा कर आप एक अच्छे वकील बन जाएं तो 6 अंकों की सैलरी बहुत आसानी से पा सकते हैं।

■ दीपिका शर्मा

पर क्या आपको नहीं लगता के इसके लिए कानून की जानकारी होने के अलावा एक लीगल प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है? एक अच्छा लॉ स्कूल ढूँढ कर डिग्री पा लेने से हर कोई वकील नहीं बन सकता। एक लॉ स्कूल में आपको कानून संबंधी तमाम पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, विधि संबंधी गेस्ट फैक्लटी आपके साथ अपने अनुभव भी बताएंगी। परंतु इतना पर्याप्त नहीं है।

सबसे पहले आप स्वयं विश्लेषण करें कि आप अपने लिए एक लीगल कॅरिअर की ही क्यों चाहते हैं? इंजीनियरिंग, शिक्षा, चिकित्सा, एमबीए या अन्य कोई क्षेत्र क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्में या नाटक देख-देखकर ही वकीलों की छवि से प्रभावित होकर आपने ये निर्णय लिया? कानून और विधि उन लोगों के लिए एक बेहतरीन क्षेत्र है जिन्हें पूरे आत्मविश्वास के

लॉ के कोर्स के बाद या तो आप कोई कानूनी संस्था से जुड़ सकते हैं या स्वतंत्र रूप से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी उद्योग इकाई से जुड़कर उनके निजी वकील का कार्यभार संभाल सकते हैं।

डायटीशियन बेहतर विकल्प

संतुलित और सही आहार हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा हमारी शारीरिक जरूरतों के मुताबिक कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है और कौन से खाद्य पदार्थ सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसका जवाब एक डाइटीशियन ही दे सकता है। जीवनशैली में आ रहे बदलावों और उनके दुष्परिणामों के चलते डाइटीशियन एक बेहतर कैरियर विकल्प के रूप में उभरा है। अलबत्ता यह पेशा अपनाकर आप अपना ही नहीं, बल्कि दूसरों की सेहत का भी ख्याल बखूबी रख सकते हैं।

बहरहाल अभी भी पोषक तत्वों के मामले में इस जरूरत को लेकर आम लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है, फिर भी सेलिब्रिटी व युवा वर्ग इस मामले में काफी सचेत होता जा रहा है। वह खाने-पीने के मामले में डाइटीशियन के मुताबिक बनाए डाइट प्लान को ही फॉलो करता है।

यही वजह कि अब युवाओं में बतौर डायटीशियन करियर बनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। एक डायटीशियन को संबंधित व्यक्ति की जीवन शैली, खाने की आदतों, सामाजिक स्तर, आयु और पाचन तंत्र की कार्यक्षमता के आधार पर आहार की सूची बनानी पड़ती है। एक डायटीशियन के रूप में आप नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग, बीमार और खिलाड़ियों तक की डाइट का चार्ट बना सकते हैं। डायटीशियन लोगों को सलाह देता है कि स्वस्थ रहने के लिए उसे किस तरह का भोजन करना चाहिए। डायटीशियन का कार्य जितना आसान दिखाई देता है वास्तव में वह उतना आसान नहीं है, क्योंकि रोगियों के लिए व्यक्तिगत आहार योजना बनाते हुए विभिन्न क्लीनिकल घटकों को ध्यान में रखना होता है। साथ ही रोगियों की जीवन शैली, खान-पान की आदतों पर भी विचार करना होता है।

कार्पोरेट क्षेत्र में माँग

डायटीशियन अमिषा तापड़िया के मुताबिक कार्पोरेट स्तर पर भी डायटीशियन की माँग बढ़ी है। पाँच सितारा होटलों में भी डायटीशियनों की सेवाएँ ली जाती हैं। यहाँ वे शेफ की मदद से ग्राहकों के लिए संतुलित आहार चार्ट तैयार करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं कि ग्राहकों को परोसा जा रहा भोजन न सिर्फ खाने लायक हो, बल्कि पौष्टिक भी हो। मौजूदा वक्त में मल्टीनेशनल कंपनियों में डिब्बाबंद और रेडी टू इट खाद्य पदार्थों का भी काफी चलन है। पिज्जा हट और जंक फूड के पार्लर सारे देश में छाए हुए हैं। यहाँ दाम की प्रतिस्पर्धा के साथ ही ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता और उचित कैलोरी आहार देने के दावे किए जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में डायटीशियनों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं। डायटीशियन पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नौसेना की प्रतिबद्धता राष्ट्र की सुरक्षा, समृद्धि सुनिश्चित करती है : प्रधानमंत्री मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना की सराहना की और कहा कि उसकी प्रतिबद्धता राष्ट्र की सुरक्षा, संरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' में नौसेना की उपलब्धियों की याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय नौसेना के अद्वितीय साहस, कार्यकुशलता और देश की रक्षा में उसके योगदान को याद करना है। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''नौसेना दिवस पर हम भारतीय नौसेना के बहादुर कर्मियों को सलाम करते हैं जो अतुलनीय साहस और समर्पण के साथ हमारे समुद्र की रक्षा करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, संरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। हमें भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास पर भी बहुत गर्व है।

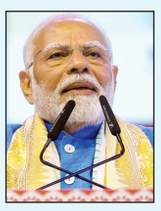

हर रेल यात्री को मिलती है 46 प्रतिशत की सब्सिडी : रेल मंत्री

नईदिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि देश में हर रेल यात्री को यात्रा टिकट पर 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56,993 करोड़ रुपये की राशि खर्च करता है। बुजुर्गों और मान्यताप्राप्त पत्रकारों को पहले मिलने वाली सब्सिडी की बहाली की संभावना के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, ''भारत सरकार की ओर से यात्रियों को कुल सब्सिडी 56,993 करोड़ रुपये की दी जाती है। हर 100 रुपये की यात्रा सेवा की कीमत 54 रुपये ली जाती है। सभी श्रेणियों के यात्रियों को 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।'' वैष्णव ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में सड़कों से पूरे देश को जोड़ा गया था, उसी तरह पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे और मझोले रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है।

वित्त मंत्री का विभिन्न पक्षों के साथ बजट पूर्व परामर्श छह से

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार यानी छह दिसंबर से विभिन्न पक्षों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करेंगी। सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत, वित्त मंत्री छह दिसंबर को प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से मिलेंगी। सीतारमण इस दौरान चालू वित्त वर्ष (2024-25) की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सात तिमाहियों के सबसे निचले स्तर 5.4 प्रतिशत रहने के बीच आगामी बजट के बारे में उनसे सुझाव लेंगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद सात दिसंबर को वित्त मंत्री की बैठक किसान संगठनों, कृषि अर्थशास्त्रियों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। यह सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला लगातार आठवां बजट होगा। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा।

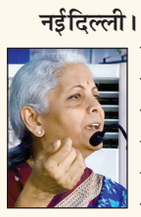

राहुल और प्रियंका को नहीं मिली संभल जाने की इजाजत

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने पर अड़ा हुआ है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जिले में पहुंचने से पहले ही रोक लिया है। संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित निषेधाज्ञा लागू है। सीमा पर भारी अराजकता देखी गई क्योंकि पुलिस ने राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर यातायात जाम हो गया। सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिससे यातायात रुक गया और कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी के बीच बैरिकेड्स पर चढ़ने का प्रयास करते देखे गए। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और यह उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्हें (संभल) जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा और पार्टी के अन्य नेता संभल का दौरा करना चाहते थे।

राहुल गांधी के संभल जाने पर भाजपा का वार

नईदिल्ली। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र में इंडी गठबंधन का बिखराव और संविधान के प्रति उनका दुराव देश की जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी दल द्वारा नियम 267 के तहत यानी सभी कार्य रोक कर किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए, इसके तहत 42 नोटिस आए थे और 9 अलग अलग नोटिस आए थे, जो इंडी गठबंधन के दो दलों ने एक विषय के लिए नहीं दिया था। त्रिवेदी ने आगे कहा कि ये स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी जो अपना एजेंडा लेकर चल रही थी, इंडी गठबंधन के बाकी दलों ने अपनी राह खुद तय कर ली। उन्होंने कहा कि सदन के पटल पर सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की विफलता के बाद राहुल गांधी रस्म अदायगी के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र संभल जाने का प्रयास कर रहे हैं।

मगरमच्छ के आंसुओं से नहीं होगा किसानों का हित: धनखड़

नईदिल्ली। राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने बुधवार को किसान विरोध का मुद्दा उठाने की विपक्ष की मांग पर आपत्ति जताई और दावा किया कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने इस मांग को मगरमच्छ के आंसू करार दिया, जिससे विपक्षी नेताओं का एक वर्ग सदन से बाहर चला गया। सदन की बैठक शुरू होते ही धनखड़ ने कहा कि वह तमिलनाडु में चक्रवात, किसानों, अडानी समूह के खिलाफ आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए चर्चा के लिए नोटिस स्वीकार नहीं कर सकते।

विपक्ष ने मांग की कि किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग पूरी की जानी चाहिए और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के अपनी मांग पर कायम रहने के बावजूद धनखड़ ने कहा कि विपक्ष केवल मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और नाटक कर रहा है। मगरमच्छ के आंसुओं से किसानों का हित नहीं पूरा होगा। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत के बाद से नियम 267 के तहत दायर कोई भी नोटिस किसानों के मुद्दों से संबंधित नहीं है।

इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के वेल के पास जमा हो गए। कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को धनखड़ की टिप्पणियों का हवाला देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि क्या किसानों से कोई वादा किया गया था और इसे पूरा क्यों नहीं किया गया।

उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री को खरी खरी सुनाई

किसानों के आंदोलन को लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मंच पर ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खरी

सुना दी और कह दिया कि किसानों को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे प्रमुख संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद किसान संकट में हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान संकट में हैं और आंदोलन कर रहे हैं तथा यह स्थिति देश के समग्र कल्याण के लिए अच्छी नहीं है।

जगदीप धनखड़ की बातें सुन कर शिवराज सिंह चौहान को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने अपने धुआंधार भाषण में कहा कि किसान यदि आज के दिन आंदोलित हैं, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। उन्होंने कहा कि जो किसान सड़क पर नहीं है, वह भी आज के दिन चिंतित हैं, आज के दिन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को आठ गुना करना है। उस आठ गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। उन्होंने कहा कि मैंने दो दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित हैं। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था की हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम अपनों से नहीं लड़ सकते। हम यह विचारधारा नहीं रख सकते कि उनका पड़ाव सीमित रहेगा, अपने आप थक जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा को परेशान थोड़ी ना करना है, दिल को चोटिल थोड़ी ना करना है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही है?

उन्होंने कहा कि हम तो रिवार्ड के बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे। जो वादा किया गया है, हम उसको देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब आह्वान किया तो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि उनका संदेश आया है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि जब कोई भी सरकार वादा करती है और वह वादा किसान से जुड़ा हुआ है तब हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रात: स्मरणीय हैं, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूँ, मैं जानता हूँ किसान क्या कुछ नहीं झेलता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था?

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री का दुनिया को संदेश है कि जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। उन्होंने कहा कि माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि अगर वादा किया था तो उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को यह कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि किसान को जो भी कीमत देंगे, उसका पांच गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आकलन बहुत संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा- जय जवान, जय किसान। उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए, जो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। उन्होंने कहा कि और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा- जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए- जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि मंत्री, एक-एक पल आपका भारी है। मेरा आप से आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताइये कि क्या किसान से वादा किया गया था? किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है।

भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया देवेंद्र फडणवीस

कहा- नतीजों से साफ, एक हैं तो सेफ हैं, शिंदे का किया धन्यवाद

मुंबई। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक में देवेन्द्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता और प्रभावी तौर पर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। इस कदम ने फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी के एक कदम और करीब ला दिया है, पिछले महीने के विधानसभा चुनावों में शानदार जनादेश हासिल करने के बाद पार्टी को अपना राज्य प्रमुख मिलने की उम्मीद है। भगवा पार्टी ने पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को अपने महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।

जैसे ही भाजपा नेताओं ने सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को अपने विधायक दल का नेता चुना, देवा भाऊ तुम आगे बढ़ो के नारे लगाए गए। फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा कि मैं विधायक दल के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने सर्वसम्मति से मुझे चुना। मैं हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षकों विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऐतिहासिक चुनाव थे और इन चुनावों ने साबित कर दिया है कि एक है तो सेफ है और मोदी है तो मुमकिन है।

भाजपा नेता ने कहा कि हमने हरियाणा के साथ अपनी जीत का सिलसिला फिर से शुरू किया है और अब महाराष्ट्र ने इतना प्रचंड जनादेश दिया है कि मैं पूरी तरह से महाराष्ट्र के मतदाताओं के सामने नतमस्तक हूं। मैं सीएम एकनाथ शिदने और डिप्टी सीएम अजित पवार और हमारे अन्य सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगले दिनों में कुछ चीजें हमारी इच्छा के अनुरूप होंगी और कुछ चीजें हमारी इच्छा के विपरीत होंगी, लेकिन हम सभी को राज्य और देश के व्यापक हित में काम करना है। हम महाराष्ट्र की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले बुधवार को कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और फडणवीस मौजूद थे। भाजपा ने सीतारमण और रूपाणी को पार्टी की महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विधायक दल की बैठक से पहले भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि महायुति के सहयोगी दल बुधवार को राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को हराकर 15 साल बाद जीता टेस्ट

जमैका। कमाल का प्रदर्शन। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद शानदार कमबैक। बांग्लादेश ने 15 साल के अंतराल के बाद वेस्टइंडीज में कोई टेस्ट जीता है। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही। वेस्टइंडीज में लगातार सात टेस्ट हारने के बाद जीत मिली। बांग्लादेश ने सबीना पार्क में चार दिनों के भीतर वेस्टइंडीज को 101 रनों से हराकर 15 साल में पहली बार कैरेबियन में कोई टेस्ट जीता है। मेहमान वेस्टइंडीज को जीत के लिए 287 रनों का लक्ष्य मिला, जबकि साढ़े पांच सत्र शेष थे। वेस्टइंडीज दो सत्र से भी कम समय तक बल्लेबाजी कर पाया और 185 रन पर आउट हो गया। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तैजुल इस्लाम को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज तस्कीन अहमद को मिला। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान जेडेन सील्स को दिया गया। सीरीज बराबर कर ली। बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान मेहदी हसन मिराज ने कहा कि खुशी बयां नहीं कर सकता। पहली पारी में नाहिद (राणा), तस्कीन (अहमद) और हसन महमूद ने कमाल का प्रदर्शन किया। दूसरी पारी के विशेषज्ञ तैजुल (इस्लाम) ने शानदार काम किया और 5 विकेट निकाले। तैजुल ने 50 रन देकर 5 विकेट लिए। ढाई साल में उनका सर्वश्रेष्ठ विदेशी आंकड़ा और वेस्ट इंडीज में उनका सबसे अच्छा आंकड़ा है। 2014 में इसी मैदान पर उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। वेस्टइंडीज के आखिरी छह विकेट 42 रन गिर गया। बांग्लादेश के लिए जैकर अली की पारी का महत्व बढ़ गया। जेकर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 91 रन बनाए। इस मैदान पर जहां सबसे सफल रन चेज 212 रन का था। यह रिकॉर्ड कायम होता।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 110 अंक चढ़ा निफ्टी 24,467 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मजबूत संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार बुधवार (4 दिसंबर) को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार मामूली बढ़त में बंद हुआ। सेंसेक्स में हैवी वेटेज रखने वाले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में खरीदारी से बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। यह लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 81,036.22 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 81,245.39 अंक तक चढ़ गया। अंत में सेंसेक्स 110.58 अंक या 0.14% की बढ़त लेकर 80,956.33 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.04 प्रतिशत आया 10.30 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,467.45 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी बैंक अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।

सेबी ने ट्रैफिकसोल एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग की रद्द

नईदिल्ली। 2024 में कई कंपनियों ने अपना आईपीओ जारी किया, जिनमें से कुछ ने शानदार मुनाफा दिया, जबकि कुछ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब एक बड़े उलटफेर के तहत ट्रैफिकसोल एसएमई आईपीओ को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जो निवेशकों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल, बीते सितंबर महीने में ओपन हुए ट्रैफिकसोल के आईपीओ की बाजार में लिस्टिंग आगे बढ़ाई गई थी और अब ये रद्द कर दी गई है। सेबी ने कंपनी से निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया है। बता दें कि ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज का इश्यू बीते सितंबर महीने की 10 तारीख को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और निवेशकों ने इसमें 12 सितंबर तक पैसे लगाए थे। इस आईपीओ का इश्यू साइज 44.87 करोड़ रुपए था और कंपनी की ओर से प्राइस बैंड 66-70 रुपए तय किया गया था।

सुजलॉन एनर्जी को मिला साल का सबसे बड़ा ऑर्डर

नईदिल्ली। सुजलॉन एनर्जी को कर्नाटक के कोप्पल क्षेत्र में जिंदल रिन्यूएबल्स से 302.4 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत सुजलॉन को ग्रीन स्टील प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए 96 अत्याधुनिक एस144 पवन टरबाइन जनरेटर की आपूर्ति करनी है। यह सुजलॉन के लिए साल का सबसे बड़ा ऑर्डर है और कर्नाटक में पहले से ही 400 मेगावाट की कैप्टिव पवन ऊर्जा परियोजना भी कंपनी के पास है। बुधवार को सुजलॉन का शेयर 65.40 रुपए के बंद भाव से 65.90 रुपए पर खुला और इसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली। सुजलॉन ने अपनी कुल ऑर्डर बुक में सीएंडआई ग्राहकों की हिस्सेदारी को 56% तक बढ़ा लिया है, जो अब तक का उच्चतम 5.4 गीगावाट है। कंपनी ने कहा कि यह सहयोग भारत के 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि में नवंबर में मामूली गिरावट

नयी दिल्ली । देश में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां नवंबर में मामूली गिरावट के साथ 58.4 रह गई, जबकि इस क्षेत्र में रोजगार में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा व्यवसाय गतिविधि सूचकांक अक्टूबर के 58.5 से नवंबर में मामूली गिरावट के साथ 58.4 रहा। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, '' भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधियों की वृद्धि दर नवंबर में 58.4 रही जो पिछले महीने के 58.5 से केवल थोड़ा सा कम है। नवंबर में सेवा क्षेत्र में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह 2005 में इस सर्वेक्षण के शुरू होने के बाद से अभी तक की सबसे तेज गति से बढ़ा।''

विकसित भारत के निर्माण में अलग भूमिका निभाएंगे औद्योगिक पार्क

धनेंद्र कुमार

आज सारे विश्व में भारत के 7 प्रतिशत से अधिक दर से हो रहे सर्वाधिक तीव्र विकास की सराहना हो रही है, जिसके बारे में विश्व बैंक, अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक और सभी वैश्विक संस्थाओं ने प्रशंसात्मक टिप्णी की है और माना है कि इस समय सारे विश्व के आर्थिक विकास के ईंजन में सर्वाधिक योगदान भारत का है।

इस सप्ताह जारी अर्न्तराष्ट्रीय संस्था 'मूडीज' ने 'ग्लोबल मेको आउटलुक' रिपोर्ट में कहा है- भारतीय इकोनॉमी 'स्वीट स्पॉट' जो 2024 में 7.2% की दर से बढ़ेगी। यह माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक, 4.34 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो जापान के 4.31 ट्रिलियन डॉलर को पछाड़ देगी । इसका एक कारण यह है कि भारत में 2023 में जीडीपी के विकास की दर 7.8% रही जो जापान के 1.9% से कहीं अधिक है। इस गति से भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की आशा है, जिसके फलस्वरूप भारत तब एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। इन सारे विकास कार्यक्रमों में देश में इंडस्ट्रियल पार्क, स्मार्ट सिटीज और उनमें विकसित हो रहे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमों का विशेष योगदान रहेगा, जैसे चीन में शेंजेन के स्पेशल इक्नॉमिक जोन और दूसरे औद्योगिक पार्कों का रहा है। इसी प्रकार अमेरिका में डेट्राइट में ऑटोमोबिल सेक्टर के विकास और सिलिकोन वेली में आईटी सेक्टर के उद्यमों के तेजी से विकास का योगदान रहा है। इसी प्रकार जर्मनी में इंजीनियरिंग उत्पादन के केन्द्रों का देश के जीडीपी के विकास में बहुत योगदान रहा है।

भारत की अर्थव्यवस्था छोटे और मध्यम दर्जों के उद्योगों (एमएसएमई) पर विशेष रूप से निर्भर है और आकंड़ों के मुताबिक देश की एक तिहाई जीडीपी उनसे आती है और लगभग 46% निर्यात भी इनके उत्पादनों पर आधारित है। रोजगार सृजन में भी एमएसएमई क्षेत्र का विशेष योगदान है जो जुलाई 2020 से जुलाई 2024 तक लगभग 21 करोड़ अनुमानित है।

औद्योगिक पार्कों और केन्द्रों में, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के कारण समन्वित और समग्र विकास से, उत्पादन के लिए सप्लाई चेन की प्रभावी क्षमता में बहुत सुधार होता है और कीमतों में कमी होती है। इसके अलावा इन पार्कों में कुछ बड़े उद्योग जो इन केन्द्रों में एन्कर उद्योगों का काम करते हैं इन अन्य उद्योगों को अनेक प्रकार से सर्पोट प्रदान करते हैं।

इन बड़े उद्योगो के विकास और आकर्षण के लिए भारत सरकार की अनेक योजनाएं, जैसे मेक इन इण्डिया, पीएलआई, पीएम गतिशक्ति इत्यादि कार्यरत हैं। कुल मिलाकर यह देश मे उत्पादन बढ़ाने के लिए ईंजन का काम करते हैं। इस समय भारत में केन्द्र और राज्यों के सहयोग से अनेक औद्योगिक कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था की धुरी बने हुए हैं और जीडीपी के विकास में पंख लगाने का काम कर रहे हैं। इनमें विशेष रूप से दिल्ली- मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चैनई इंडस्ट्रियल कोरिडोर उल्लेखनीय हैं। इधर अनेक राज्यों में नए-नए कॉरिडोर और औद्योगिक केन्द्र बन रहे हैं जो देश और क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और देशभर में मध्यम और छोटे शहरों के विकास में भी तेजी ला रहे हैं। इसी प्रकार यू.पी. में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश की रक्षात्मक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें 6 केन्द्र होंगे- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और युगांतरकारी पहल के अन्तर्गत एनआईसीडीपी (राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम) की घोषणा की जिसमें देशभर में 28,600 करोड़ रुपये के निवेश से 11 राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे जिनमें बड़े-बड़े एंकर उद्योग और छोटे और मंझले दर्जे के एमएसएमईज विकसित होंगे और 2030 तक इनके द्वारा 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात संभव हो पाएगा जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को पूर्ण करने तेजी से करेंगे प्रयास

हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी निर्णायक लड़ाई - साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।

बैठक में सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

पूर्व सीएम के बयान पर पंकज झा का करारा जवाब, कहा-

भूपेश ने किया वेतनभोगियों का अपमान, ऐसे कैसे चलेगा दाऊ? खेल का नियम एक ही रखिए

रायपुर. पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर सीएम के सलाहकार पंकज झा ने पटलवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है. उन्होंने ट्वीट कर कई व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी है. झा ने कहा, वेतनभोगी होना शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह भारत के लाखों लोगों की मेहनत और ईमानदारी से जुड़ा हुआ है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बयान को वेतनभोगियों का अपमान बताया है. झा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में वेतनभोगियों और सरकारी सलाहकारों को राजनीतिक बयानबाजी की खुली छूट दी गई थी, अब भाजपा के सलाहकारों के बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं. ऐसे कैसे होगा दाऊ? खेल का नियम एक ही रखिए, तब खेलने में आनंद आएगा न? झा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का हवाला देते हुए कहा कि एक नागरिक के रूप में उनके पास अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है.

पंकज झा ने कहा है कि आप विश्व के सार्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में अनाप-शनाप बोल सकते हैं, वह आपका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन मैं एक 'वेतन पर पलने वाला' हो गया, जो एक साधारण ट्वीट भी नहीं कर सकता? क्या आप मुसोलिनी के अवतार हैं या इटली से इतना अधिक प्रभावित हैं? स्मरण कीजिए आप कि आपकी पार्टी और आप 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे व्यक्तित्व के बयानों पर कैसी प्रतिक्रिया देते थे, किस तरह जानबूझ कर अपने जिला स्तर के कार्यकर्ता का बयान पूर्व सीएम के विरुद्ध छपाते थे, ताकि वे अधिक से अधिक वे अपमानित महसूस करें. याद कीजिए अपने उस अपराध को, जब वर्तमान मुख्यमंत्री और सहज-सरल, सौम्य नेता, तब के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के खिलाफ आप किस तरह के बयान देते थे? याद दिलाएं आपको? आपने अपनी तुनकमिज़ाजी और पद के अहंकार में हमारे तब के प्रदेश अध्यक्ष साय को कहा था कि उनके दिमाग में गोबर भरा है, जिससे आपको बिजली बनाना है.

एक राष्ट्रीय आदिवासी नेता जो अनेक बार सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, उनके ख़िलाफ़ क्या बिना वेतन पर पलते हुए ही आपने ऐसा असंसदीय विषवमन किया था क्या? आप सदन तक में 'दो-गला' जैसा अमर्यादित शब्द उच्चारित करते थे. अगर आपको याद हो, तो आपके और कांग्रेसियों के ऐसे सौ अपशब्दों की हमने सूची जारी की थी. वे सारे बयान क्या बिना 'तनख्वाह पर पलते हुए ही' दिया जा रहा था क्या?

मुख्यमंत्री के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं, सैलरी वाले सलाहकार बोल रहेः बघेल

बता दें कि दो दिन पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि इनके पास कोई काम नहीं है. जो सैलरी पर रखे गए हैं, वो ऐसी बातें फैला रहे हैं. बीजेपी में अशांति है. बीजेपी के तमाम बड़े नेता खाली बैठे हैं. प्रेम प्रकाश पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल सब खाली बैठे हैं. ये कौन सलाहकार है, कहां का रहने वाला है? छत्तीसगढ़ की सरकार बिहार से चलेगी. बीजेपी में इतना राजनीतिक अकाल पड़ गया है? राजनीतिक बयान राजनीतिक दे तो कोई बात है, क्या बीजेपी में इतना अकाल पड़ गया कि विष्णुदेव साय के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है. तनख्वाह में रखे गए लोग बोलेंगे.

साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती

जिसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना आवश्यक : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है।

मुख्यमंत्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।

कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे।

पूरे प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रो में अव्यवस्था का आलम

रायपुर। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धान खरीदी केन्द्र चलो अभियान चलाया। जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी धान खरीदी केन्द्रों में गये जहां उन्होंने देखा पूरे प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था से किसान परेशान है। सरकार की कोशिश है कम से कम धान खरीदी की जाये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार खरीदी केन्द्रों में जानबूझकर अव्यवस्था बनाकर रखी है। प्रदेश की सभी सोसायटियों में यह परेशानिया देखने को मिली। बारदाने की कमी है, जिससे किसानों को धान बेचने में परेशान होना पड़ रहा। टोकन की व्यवस्था अव्यवहारिक है, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा, नंबर ही नहीं आ रहा। किसानों को भुगतान मात्र 2300 रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा में जो तौलाई हो रहा है उसमें 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम अधिक तौला जा रहा है। अनावरी रिपोर्ट कम बनाई गयी है तथा खरीदी भी 21 क्विंटल के हिसाब से नहीं हो रही है। कहीं-कहीं ही पूरा धान खरीदा जा रहा। सोसायटियों में धान का उठाव नहीं होने के कारण जगह की कमी है। धान के बोरे जाम है। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये, 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बारदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है।

टोकन कटने की तारीख से 7 से 10 दिन बाद धान बेचने के लिये किसानों को बुलाया जा रहा है। 15 दिन बाद तक का भी टोकन नहीं मिल रहा। किसानों से पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा है। अनावरी रिपोर्ट गलत बनाया जा रहा जिसके आधार पर मात्र 9 से 12-14 क्विंटल धान खरीदा जा रहा। किसानों से पूरा 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। बड़े किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे उनकी बारी ही नहीं आ रही है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

बिजली की कटौती और बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी जनता पर अत्याचार

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नही दे पा रही है ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर से 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दिया, इसके पहले भी साय सरकार ने बिजली के दाम में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था। यह जनता पर अत्याचार है। अभी तक सरकार ने एक साल में 17.31 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ा दिये है। प्रदेश की जनता महंगाई से पीड़ित है इस दशा में बिजली के दर में बढ़ोतरी करना महंगाई से जख्मी जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। पिछले 11 माह से बिजली के बिल दुगुने आ रहे है। पिछले माह के बिल में सुरक्षा निधि के नाम पर उपभोक्ताओं से बिल के साथ 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूला गया था। आम आदमी बिजली के दाम बढ़ने से परेशान है। स्मार्ट मीटर लगा कर उपभोक्ता को लूटने की तैयारी भाजपा सरकार कर रही है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था.

भाजपा दिखावे के लिए दिव्यांगजन सम्मान दिवस मना रही

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के दिन भाजपा सरकार की पुलिस ने दिव्यांग जनों के साथ जो बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया है, उन्हें सड़क पर घसीट घसीट कर मारा गया है यह बेहद निंदनीय है। भाजपा सरकार में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सम्मान समारोह सिर्फ राजनीतिक नोटंकी दिखावा था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में दिव्यांगजनो से जो वादा किया था उसे पूरा करने की मांग को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। पहले उन दिव्यांग जनों को बंधक बनाया गया। लाठियों से पीटा गया क्या यही दिव्यांगों के प्रति भाजपा सरकार का सम्मान है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने बड़े-बड़े वादा किया जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। अब जिस वर्ग से वादा किया गया था, वो वर्ग अगर वादा पूरा करने की मांग करते हैं, तब उन पर लाठियां बरसाई जाती है। भाजपा का यही दोगला चरित्र है। दिव्यांगजन की मांग जायज है। सरकार तुरंत उसे पर विचार करें और फैसला ले दिव्यांग जनों से की गई मांगों को पूरा करें दिव्यांग जनों पर की गई बर्बरता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पर कार्यवाही करें।

अग्निवीर अभ्यर्थी कचरा गाड़ी में ढोए जा रहे हैं

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के कुशासन की पोल रोज रोज खुल रही है। बेरोजगारी की मार भोग रहे युवा 4 साल के लिए ही सही, देशसेवा का जज्बा लेकर अग्निवीर के रूप में रोजगार पाने कड़ाके की ठंड में बदहाल घूमने मजबूर हैं और प्रदेश के मंत्री व्यवस्था दुरूस्त करवाने की बजाय फीता काटने और फोटो बाज़ी में लगे रहे। रायगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है। सैकड़ो युवा रायगढ़ में ठंड में ठिठुरते भटकते रहे और प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी अग्निवीर भर्ती कार्यक्रम का फीता काटकर निकल लिये। अग्निवीर के रूप में देश सेवा का अवसर ढूंढ रहे युवाओं को भारी ठंड में पैदल भटकना पड़ रहा है। रायगढ़ बस स्टैंड, केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों में बड़ी संख्या में युवक बस का इंतजार करते रहे। संवेदनहीन सरकार की बदइंतजामी के चलते कुछ युवाओं को नगर निगम के कचरा ढोने वाली गाड़ी में सवार होना पड़ा। चाय, पानी, आवास और भोजन कुछ भी नसीब नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के दावों की कलाई खुल चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 4 से 12 दिसंबर तक रायगढ़ स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों की भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा ह.

हादसे में मोहन ने गंवाई हाथ, अब कृत्रिम हाथों से काम होगा आसान

रायपुर। एक वक्त था जब एक हाथ से काम आसान नहीं हो पाता था। तकलीफें बहुत होती थी, लेकिन समस्याओं को दूर करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते है। क्योंकि उनकी वजह से आज मुझे कृत्रिम हाथ मिला और उन हाथों से अब सब काम भी आसान हो जाएगा। यह कहना है दुर्ग निवासी श्री मोहन कन्हाई। दिव्यांग मोहन यह कहते है कि नि:शुल्क कृत्रिम फंक्शनबेल हाथ मिलने से काफी खुशी हुई। पहले रोजगार की चिंता अक्सर सताते रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों हाथ से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो रोजगार भी मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि यह अत्याधुनिक कृत्रिम हाथ 36 से ज्यादा ग्रिप पैटर्न बनाने में सक्षम है और इसे एंड्राइड और साफ्टवेयर एप से भी संचालित किया जा सकता है। साथ ही, यह कृत्रिम हाथ चार्ज भी किया जाता जाता है। यह कृत्रिम हाथ 35 किलो तक वजन उठाने में सक्षम हैं, जिससे उपयोगकर्ता को अपने दैनिक कार्यों में सहूलियत मिलती है। इस तकनीकी डिवाइस को पोलैंड की एक कंपनी ने 13 लाख रुपये की लागत से निर्मित किया है, जो कि एक उन्नत और किफायती विकल्प है।

महतारी वंदन की 10वी किस्त जारी होने पर भाजपा ने किया स्वागत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त की राशि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधे अंतरित होने के बाद कहा है कि यह कांग्रेस के उस झूठ का करारा जवाब है, जो वह इस योजना को लेकर शुरू से फैलाने में लगी हुई थी। श्रीमती साहू ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर झूठ बोलकर हर बार मुँह की खा रही है, फिर भी झूठ बोलने, षड्यंत्र रचने और अराजकता फैलाने के मंसूबे पालने से बाज नहीं आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती साहू ने कहा कि दरअसल कांग्रेस वादाखिलाफी में माहिर है, इसलिए उसे हर जगह पीलिया के मरीज की तरह सबकुछ पीला-पीला नजर आता है, लेकिन प्रदेश की जनता-जनार्दन का यह दृढ़ विश्वास है कि भाजपा जो कहती है, वह करती है। प्रदेश की 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपए की राशि की 10वीं किश्त मंगलवार को अंतरित की गई है। माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार और भाजपा को काम करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। महतारी वंदन योजना के कारण माताओं-बहनों की आँखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक भाजपा और प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा संतोष है।

पुलिस ने गैंती गैंग का किया पर्दाफाश

3 चोर समेत दो ज्वेलर्स और सहयोगियों को किया गिरफ्तार, 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम

रायपुर। पुलिस ने राजधानी रायपुर की आवासीय कॉलोनियों के सुनसान मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंती गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर चोरों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह थाना मुजगहन, विधानसभा, तिल्दा नेवरा एवं मंदिर हसौद के सुनसान मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इस दौरान सेंध लगाने के लिए ये चोर गैंती और पेचकस का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नगदी, दोपहिया वाहन और अन्य चोरी के सामान भी बरामद किया हैं।

बता दें कि पुलिस ने गैंती गैंग के जिन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है उनमें सृजन शर्मा उर्फ स्वराज, उमेश उपाध्याय और सफीक मोहम्मद शामिल हैं। इनमें सृजन शर्मा उर्फ स्वराज पूर्व में भी चोरी और नकबजनी के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह और उसके साथी चोरी के जेवरातों को अपने परिचित ज्वेलर्स के पास बेच देते थे, वहीं कुछ जेवरातों को वित्तीय कंपनियों में गिरवी रखकर वह नगदी प्राप्त करते थे। पुलिस ने इन फाइनेंस कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है।

पुलिस ने इस गिरोह के संगठित अपराध में शामिल अन्य सहआरोपियों और ज्वेलर्स को धारा 111 और 317 बी.एन.एस. के तहत भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गैंती गैंग के चोर सोने-चांदी के जेवरातों को अपने परिचित ज्वेलर्स दुकान के कारिगरों और वर्कर हर्ष कुमार बंजारे उर्फ गोविंदा, मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी, मेवालाल कश्यप, हेमंत कश्यप, कमलजीत कश्यप उर्फ जीतू और जय कुमार सोनी को देते थे, जिसके बाद यह सभी जेवरातों को गलाकर ज्वेलर्स दुकान के मालिक बिलासपुर निवासी राजेश कुमार सोनी, उरला निवासी भूषण कुमार देवांगन और मुंगेली निवासी जय कुमार सोनी को बेच देते थे।

पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर उनके कब्जे से 316 ग्राम सोना, 2 किलो 900 ग्राम चांदी, घटना प्रयुक्त 5 नग मोबाइल फोन, 2 नग दोपहिया और वारदात में इस्तेमाल की गई गैंती, पेचकस जब्त किया है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये आंकी गई है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जिला दुर्ग धान खरीदी केंद्र खोपली का औचक निरीक्षण किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग पूर्व विधायक अरुण वोरा के साथ जिला दुर्ग धान खरीदी केंद्र खोपली का औचक निरीक्षण किया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, मात्र एक इलेक्ट्रॉनिक तौलाई मशीन उपलब्ध है जिसके कारण टोकन के लिए किसानो को लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है किसानो ने धान की कटाई और मिंसाई कर लिया है उसके पास धान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है इसको लेकर किसानो में असंतोष व्याप्त हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बताया कि, खरीदी प्रारंभ होने के बाद धान का उठाव न तो कस्टम मिलर के द्वारा किया गया है और न ही विपणन संघ के द्वारा संग्रहण केन्द्रो में भंडारण प्रारम्भ किया गया है जिससे खरीदी केंद्र में जाम की स्थिति निर्मित हो सकती है, किसानों को केवल समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया जा रहा है मोदी की गारंटी के अनुसार एकमुश्त

रु. 3100/- प्रति क्विंटल की दर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, भारत सरकार द्वारा प्रदाय किये गये नए बारदानों का औसत वजन निर्धारित वजन से कम है और गुणवत्ता अच्छी नहीं है, धान खरीदी केन्द्रो में सुखन मान्य नहीं है जबकि भारत सरकार द्वारा आधा प्रतिशत सुखन मान्य है परन्तु साय सरकार इसका लाभ सोसायटियों को नही दे रही है। मंडी लेबर चार्ज की अधिसूचित दर रु 34.10 प्रति क्विंटल है परन्तु इस दर के अनुसार राशि का भुगतान सोसायटियों को नहीं किया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.